



उत्तरशक्ति

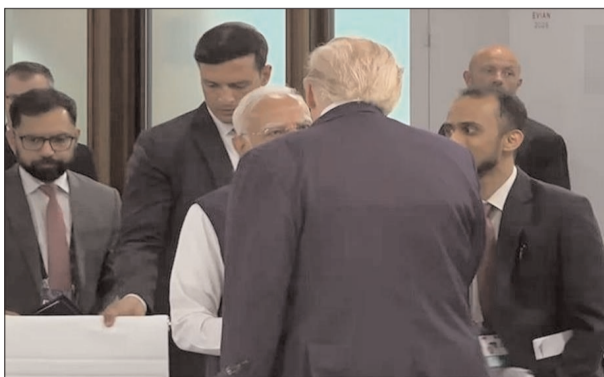
हर खबर निष्पक्षता के साथ

जी7 सम्मेलन में गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और ट्रंप

एवियॉन, 16 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फ्रांस के एवियॉन में जी7 सम्मेलन के दौरान एक दूसरे का अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की। द्विपक्षीय संबंधों में जारी तनाव के बीच, 16 महीनों में दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। मोदी और ट्रंप गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दिखे और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बातचीत भी की। दोनों नेताओं की बुधवार को सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। तत्काल यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्या बातचीत की। पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री के अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए वाशिंगटन जाने के बाद से मोदी और ट्रंप की यह पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं की बुधवार को होने वाली बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए चल रही

बातचीत और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों सहित संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यह व्यापार समझौता एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिसकी परिकल्पना पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान की गई थी। मोदी और ट्रंप प्रथम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी अहम वैश्विक चुनौतियों पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रबियो की पिछले महीने भारत यात्रा के बाद, दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। रबियो ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से उन्हें 'निकट भविष्य' में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने भारत को हिंद-प्रशांत को लेकर तैयार अमेरिकी नीति का



'आधार' बताया था। ट्रंप द्वारा मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने में अहम भूमिका निभाने के दावे किये जाने और अमेरिका की ओर से भारत पर दंडात्मक शुल्क लगाए जाने के बाद नयी दिल्ली-वाशिंगटन के रिश्तों में भारी गिरावट आई।

भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष रुकने के बाद ट्रंप ने बार-बार और सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्होंने दो पड़ोसी देशों के बीच सैन्य

पक्षों ने रिश्तों को सुधारने की कोशिशें कीं और जल्द ही आपसी हित वाले व्यापार समझौते को अमली जामा पहनाने की दिशा में काम शुरू किया।

पिछले हफ्ते, दोनों देशों के रिश्तों में तब नए सिरे से तनाव पैदा हो गया जब ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना ने तीन वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया और इन हमलों में तीन भारतीय नौविक मारे गए। हमलों में एक जहाज पर सवार तीन भारतीयों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत ने अमेरिका के दूतावास प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया और उनसे कहा कि भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी सेना के 'जानलेवा और घातक' हमले 'स्वीकार्य नहीं' हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रबियो के समक्ष यह मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी जी7 सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

बंगाल में टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी पर अंडा अटैक, कोर्ट ले जाते वक्त लगे 'चोर' के नारे

बर्धमान, 16 जून। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के रानीगंज शहर में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता सौमित्र बनर्जी पर अंडे फेंके गए। उन्हें एक बीजेपी नेता की शिकायत पर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कोर्ट ले जा रही थी। मौके के वीडियो में दिख रहा है कि जब बनर्जी को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तो भीड़ उन पर अंडे फेंक रही थी और चोर, चोर, चोर के नारे लगा रही थी। पुलिसकर्मियों ने तुरंत दखल दिया, हालात को काबू में किया और व्हाट्सएप को सुरक्षित कोर्ट पहुँचाया। बीजेपी नेता रवि केशरी की शिकायत पर सौमित्र बनर्जी को गिरफ्तार किया गया। उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है।



और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के घर के बाहर इसी तरह निशाना बनाया गया था। जब वह ममता बनर्जी के घर से निकल रहे थे, तो एक स्थानीय युवक ने उन पर अंडा फेंका। आरोपी, जिसकी पहचान चंदन के तौर पर हुई है, ने बाद में दावा किया कि उसने तृणमूल कांग्रेस से नाराजगी के कारण ऐसा किया। घोष ने बताया कि वह ममता बनर्जी के घर एक बैठक में शामिल होने गए थे और उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। घोष ने आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाने वाले

बीजेपी के उपद्रवी थे और उन्होंने अपनी आँख बचा ली वरना वह खराब हो सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय पुलिस वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया।

कुणाल घोष ने कहा, मैं ममता बनर्जी के घर एक मीटिंग में शामिल होने आया था। मीटिंग के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो रोज की तरह पत्रकारों ने मुझसे इंटरव्यू के लिए कहा। इसलिए, मैं उनके सवाल को जवाब दे रहा था... तभी दो लड़कों ने मुझे निशाना बनाया और मुझ पर अंडा फेंका। उनमें से एक ने अंडा फेंका। मैंने अपनी आँख बचा ली, वरना वह खराब हो सकती थी। ममता बनर्जी को 'कैटेगरी' की सुरक्षा मिलती है, फिर भी उनके घर के पास इस तरह की घटना हुई; यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मायावती

लखनऊ, 16 जून। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को साधने की रणनीति तैयार कर दी है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित और कल्याण केवल बसपा सरकार में ही निहित है। बसपा की ओर से मंगलवार को जारी बयान में यह बात कही गई है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 2007 में प्रदेश में बसपा की पहली पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में ओबीसी समाज का ऐतिहासिक योगदान था। अब 2027 के चुनाव में उस इतिहास को दोहराने के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है।



उन्होंने कहा है कि पिछले कई दिनों से लखनऊ में चल रही बैठकों में ओबीसी जनाधार बढ़ाने और कार्यकलापों की गहन समीक्षा की

निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि बसपा ने अपनी स्थापना के बाद मंडल रिपोर्ट लागू करवाई और सरकार में आने पर ओबीसी समाज को संविधान के अनुरूप आत्म-सम्मान के साथ जीने का हक दिया।

पार्टी की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बसपा सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज जैसे महापुरुषों को पूरा आदर-सम्मान देकर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को मजबूत आधार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दलित और ओबीसी के विकास के लिए बसपा सरकार ने पहली बार अलग मंत्रालय, आयोग और योजनाएं बनाई लेकिन अब ये काम कागजों तक सिमट गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों की नीयत और नीति में ईमानदारी नहीं, बल्कि खोट ज्यदा है। इसी कारण ओबीसी समाज की हालत नहीं सुधर रही।

संघ को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है: मोहन भागवत

नई दिल्ली, 16 जून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फर) प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि संघ को किसी के सामने जवाब देने की जरूरत नहीं है। दरअसल, प्रियांक खरगे ने हाल ही में मोहन भागवत को पत्र लिखकर फर को रजिस्टर्ड कराने और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए थे। इस बयान के बाद दिसायसी माहौल गरमा गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से "अहंकार छोड़कर" आनन का पालन करने को कहा है। खरगे ने साथ ही कहा कि एक तरफ तो आरएसएस दावा करता है कि उसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है वहीं दूसरी ओर वह समाज और राजनीति पर व्यापक प्रभाव रखता है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत



द्वारा संघ को पंजीकृत कराने की मांगों को खारिज किए जाने के जवाब में सोमवार देर रात एक पोस्ट में यह बात कही। खरगे ने कहा कि भगवत का यह दावा सबसे अधिक चिंताजनक है कि आरएसएस किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा "जबकि वे करदाताओं के पैसे से मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं और प्रोटोकॉल का लाभ उठाते हैं। खरगे ने कहा कि यह ऐसी मानसिकता को दर्शाता है

कर देना चाहता हूँ। आरएसएस को एक सांस्कृतिक संगठन होने का पूरा अधिकार है, यह उनका निर्णय है। लेकिन यह संभव नहीं है कि वह समाज और राजनीति पर व्यापक प्रभाव भी रखे और बार-बार यह भी दावा करे कि उसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, इसलिए वह किसी भी सार्वजनिक जवाबदेही के लिए बाध्य नहीं है। स्वयं भाजपा भी आरएसएस को अपनी वैचारिक मार्गदर्शक मानती है और सार्वजनिक जीवन पर उनका प्रभाव स्पष्ट और निर्विवाद है।

खरगे ने कहा कि कानून के तहत औपचारिक मान्यता मिलने से इस विरोधाभास का समाधान एक बार और हमेशा के लिए हो जाएगा। केरल के त्रिशूर में रविवार को एक बातचीत के दौरान भागवत ने आरएसएस को पंजीकृत कराने की मांगों को खारिज कर दिया था और कहा था कि संगठन न तो गोपनीय रूप से काम करता है और न ही सार्वजनिक जांच से बाहर है। उन्होंने कहा कि संगठन के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह अपनी गतिविधियां खुले रूप से संचालित करता है।

सिक्वोरिटी लाइजन् प्रोटोकॉल प्राप्त है और आरएसएस के अन्य लोगों को भी करदाताओं द्वारा वित्तपोषित प्रोटोकॉल मिलते हैं, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या यह संगठन उन्हीं कानूनी मानकों का पालन करता है, जो सभी के लिए अपेक्षित हैं।

खरगे ने कहा कि कानून के तहत औपचारिक मान्यता मिलने से इस विरोधाभास का समाधान एक बार और हमेशा के लिए हो जाएगा। केरल के त्रिशूर में रविवार को एक बातचीत के दौरान भागवत ने आरएसएस को पंजीकृत कराने की मांगों को खारिज कर दिया था और कहा था कि संगठन न तो गोपनीय रूप से काम करता है और न ही सार्वजनिक जांच से बाहर है।

उन्होंने कहा कि संगठन के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह अपनी गतिविधियां खुले रूप से संचालित करता है।

बीजेपी को रोकने के लिए ओवैसी का बड़ा दांव, यूपी 2027 में विपक्ष से गठबंधन को तैयार

हैदराबाद, 16 जून। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए दूसरे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। 16 जून को उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान, ओवैसी ने राज्य में AIMIM को पहले चुनावों में मिली हार को माना, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि पार्टी अब जमीनी स्तर पर ज्यादा जोर-शोर से प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने पिछली बार, 2017 में चुनाव लड़ा था, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली... हम और ज्यादा कोशिश कर



रहे हैं। हमने अपनी पिछली गलतियों और कमियों को सुधारा है। AIMIM अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए राज्य पार्टी नेता शौकत अली और उनकी टीम को पूरे उत्तर प्रदेश में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि वड में 2027 में चुनाव होने हैं, इसलिए हमारी पार्टी के नेता शौकत अली और पूरी टीम इसकी तैयारियों में जुटी हुई है।

तमिलनाडु में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 1.28 लाख रुपये का कर्ज, विजय सरकार का श्वेत पत्र

तमिलनाडु, 16 जून। विजय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति पर जारी एक श्वेत पत्र के अनुसार, तमिलनाडु की कुल वित्तीय देनदारियां बढ़कर अनुमानित 13.18 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं, और राज्य का बकाया प्रत्यक्ष कर्ज 10 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। वित्त मंत्री एन. मेरी विल्सन द्वारा पेश की



गई वित्तीय स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि एमके स्टालिन के नेतृत्व

वाली डीएमके सरकार के तहत पिछले पांच वर्षों में राज्य पर कर्ज का बोझ लगभग दोगुना हो गया है और तमिलनाडु में पैदा होने वाले हर बच्चे पर असल में 1.28 लाख रुपये का कर्ज है। तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति पर 'श्वेत पत्र' जिसमें पिछली एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार से मिली वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई है। विजय द्वारा पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद की गई पहली

बड़ी घोषणाओं में से एक था। डॉक्यूमेंट के अनुसार, राज्य का सीधा कर्ज पांच साल पहले के लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर अभी लगभग 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जब ऑफ-बजट उधार, गारंटी और दूसरी देनदारियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो राज्य पर कुल वित्तीय बोझ का अनुमान 13.18

लाख करोड़ रुपये लगाया जाता है। मंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में जमा हुआ कर्ज, उससे पहले के छह दशकों में जमा हुए कुल कर्ज से भी ज्यादा है।

उन्होंने आगे कहा कि उधार का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बनाने के बजाय रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में इस्तेमाल किया गया है।

DAKS REHAB CENTRE

(PARALYSIS PHYSIOTHERAPY CENTER AND OLD AGE HOME)

Contact us: 9820519851

विलिंडिंग नंबर 3, फ्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीवी नगर मुंबई-37

- * Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
- * बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
- * वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
- * DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
- * NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
- * चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
- * एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
- * पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
- * मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
- * विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
- * मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तियों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

NEW LIGHT CLASSES

TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheela Bldg. Near Dianond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra

ADMISSIONS OPEN

ALL OVER INDIA

ENROLL NOW

SMART CLASSROOM

(ONLINE/OFFLINE)

Courses Offered

- Std. XI & XII (Sci.)
- MHT-CET
- NEET
- Polytechnic & Engg
- JEE
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

TIWARI'S SARASWATI CLASSES

Since 1992

Parents' First Choice for 34+ Years

Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director

ADMISSIONS OPEN

9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE

NEET | JEE | MHT-CET

10 DAYS FREE DEMO

Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)

- ✓ 34+ Years of Academic Excellence
- ✓ Experienced & Dedicated Faculty
- ✓ Personal Attention
- ✓ Printed Notes & Regular Tests
- ✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams

Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai 400055

Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukrupa Hotel, Sion (West), Mumbai

Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

चिन्ताजनक है महंगी होती दवाइयां, महंगा होता इलाज



-ललित गर्ग

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने के स्वप्न के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बार-बार दोहराई जा रही है। बड़े-बड़े बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां और आर्थिक विकास के दावों के बीच एक प्रश्न बार-बार सामने खड़ा हो जाता है-क्या ऐसा भारत वास्तव में विकसित कहलाएगा, जहाँ एक सामान्य नागरिक बीमारों के कारण कर्ज में डूबने को विवश हो जाए? जहाँ इलाज और दवाइयों की बढ़ती कीमतें जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय करने लगे? जहाँ स्वास्थ्य सेवा अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक सामर्थ्य का विषय बन जाए? ऐसे समय में जब महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अधिनियम (एन.पी.पी.ए.) द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं और टीकों की कीमतों में भारी वृद्धि को अनुमति देना गंभीर चिंता का विषय है। कैंसर की कुछ दवाओं, एंटी-डेटेनस सीरम और बच्चों के आवश्यक टीकों की कीमतों में लगभग पचास प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति ने लाखों परिवारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। यह निर्णय केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और जनकल्याणकारी शासन की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी अपने



इलाज का खर्च अपनी जेब से वहन करते हैं। बीमारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं रह जाती, वह आर्थिक संकट में भी बदल जाती है। एक समय था जब कहा जाता था कि व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के कारण कर्ज में डूबता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि किसी गंभीर बीमारी का इलाज पूरा परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग या अन्य जटिल बीमारियों का उपचार लाखों रुपये की मांग करता है। ऐसे में यदि जीवनरक्षक दवाइयों की कीमतें भी लगातार बढ़ती रहें तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा लाभ्य असंभव हो जाएगी। एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कीमत बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में वृद्धि और बाजार में संभावित कमी का तर्क दिया है। उनका कहना है कि यदि दवा कंपनियाँ लागत भी नहीं निकाल पाएंगी तो वे उत्पादन बंद कर सकती हैं, जिससे मरीजों को आवश्यक दवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है। किसी भी उद्योग को जीवित रहने के लिए उचित लाभ आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जीवनरक्षक दवाओं को सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह देखा जा सकता है? क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ कमाने की सीमा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जाना चाहिए?

स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। दुर्भाग्य से भारत में इन दोनों क्षेत्रों में व्यवसायीकरण का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। निजी अस्पतालों की बढ़ती फीस, महंगे परीक्षण, अनावश्यक जांचें, चिकित्सा उपकरणों का भारी खर्च और अब दवाइयों की बढ़ती कीमतें मिलकर आम नागरिक को असहाय बना रही हैं। चिकित्सा सेवा धीरे-धीरे सेवा के बजाय उद्योग में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र कम और कॉरपोरेट प्रतिष्ठान अधिक प्रतीत होने लगे हैं। रोगी अब मरीज नहीं, बल्कि ग्राहक की तरह उभर खड़े लगता है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी गहरा करती है। आज भी देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मुख्यतः उन्हीं लोगों को उपलब्ध हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों, सीमित संसाधनों और अपर्याप्त सुविधाओं के भरोसे है। आमो व्यक्ति अत्याधुनिक अस्पतालों और महंगे उपचारों का लाभ उठा सकता है। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही वह भारत है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक जनहितकारी योजनाएँ लागू हुई हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना ने लाखों लोगों को राहत भी प्रदान की है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना ने सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक व्यापक विसंगतियाँ अभी भी रहती हैं। यदि दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहें और निजी स्वास्थ्य सेवाएँ अनियंत्रित होती जाएँ, तो इन योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाएगा। वास्तविक चुनौती यह है कि स्वास्थ्य को बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ने के बजाय उसे जनकल्याण के केन्द्र में रखा जाए। सरकार का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों। जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दवा खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आवश्यक दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष सहायता और सब्सिडी भी दे सकती है, ताकि लागत बढ़ने का पूरा बोझ मरीजों पर न पड़े।

इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा और व्यापक होना चाहिए। अनेक गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार ऐसे हैं जो किसी भी बीमा सुरक्षा से वंचित हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में वे अपनी जीवनभर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। स्वास्थ्य बीमा केवल अस्पतालों में भर्ती होने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यक दवाओं और दीर्घकालिक उपचारों की भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकार समय-समय पर दवा कंपनियों की लागत संरचना और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्र समीक्षा करे। यदि वास्तव में लागत बढ़ी है तो उसका प्रमाण सार्वजनिक होना चाहिए। पारदर्शिता से जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और अनावश्यक मूल्यवृद्धि पर भी रोक लगेगी। स्वास्थ्य नीति का मूल उद्देश्य कंपनियों के लाभ और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए।

वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, तेज रफतार सड़कों और बढ़ती जीडीपी से नहीं बनेगा। उसका वास्तविक मूल्यकेंद्र इस आधार पर होगा कि वहाँ का सबसे गरीब नागरिक कितना सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ है। यदि एक किसान, मजदूर, कर्मचारी या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति बीमारी के समय सम्मानपूर्वक इलाज प्राप्त नहीं कर सकता, तो विकास के दावे अंधेरे रह जायेंगे। यदि आवश्यकता केवल दवाइयों की कीमतों पर बहस करने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की समग्र समीक्षा करने की है। यह स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं, बल्कि मौलिक मानवीय अधिकार है। जिस राष्ट्र में नागरिकों को स्वस्थ जीवन का अक्सर नहीं मिलता, वहाँ विकास की चमक भी फीकी पड़ जाती है। समय आ गया है कि सरकार, नीति-निर्माता, चिकित्सा जगत और समाज मिलकर यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का सशक्त उपकरण बने। अन्यथा विकसित भारत का सपना केवल अंधेरे में चमकेगा, जबकि आम आदमी बीमारी, कर्ज और असहायता के अंधकार में संघर्ष करता रहेगा। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते भारत के सामने यही सबसे बड़ी नैतिक और मानवीय चुनौती है, जिसका समाधान आज ही तलाशना होगा।

सबकी नजर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा समझौते पर



अशोक भाटिया

नेतृत्वाहू ने जवाब देते हुए कहा, इजराइल अपनी धरती पर गोलीबारी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घोषणा के बाद, युद्ध और तेल आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता कम होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब पांच प्रतिशत की गिरावट आई और यह 83 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। मोदी ने कहा कि इस समझौते के क्रियान्वयन से क्षेत्र में शांति, स्थिरता और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। ब्रेट वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 83.33 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हो गईं, जो पिछले सप्ताह तक 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं, और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी, जिसके कारण वृद्धि हुई, तुरंत हटा ली जाएगी। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला संकरा जलमार्ग वैश्विक तेल का एक प्रमुख स्रोत है क्योंकि यह दुनिया के कच्चे तेल के प्रवाह का लगभग 20 प्रतिशत है। अमेरिका ने गारंटी दी है कि कोई नौसैनिक नाकाबंदी नहीं होगी। इसलिए ट्रंप की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही यह घोषणा की गई कि ईरान ने भी समझौते के मसौदे पर सहमति जताई है। इसलिए पिछले कई दिनों से दोनों देश 'एक बात कहते हैं' और वे उसे अस्वीकार करते हैं' के चक्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिश्चितता से कुछ निश्चित का स्वागत है। ये भी स्वाभाविक है कि ईरान की कमी से

चल रहे देशों ने राहत की सांस ली है। इजरायल की जिद ने दुनिया को एक नई स्थिति में डाल दिया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया, ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला खामेनेई को खतम कर दिया और सैन्य नेतृत्व के शीर्ष अधिकारियों को काट दिया। वही विनाशकारी भी साबित हुआ। मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी अरब देश संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में इस प्रतिरोध से अधिक प्रभावित थे। यह आज भी वैसा है। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत के तेल समृद्ध देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्य पहचान थे, और ईरान ने उन्हें इस बात से अवगत कराया कि यहाँ से उनसे निपटना कितना मुश्किल होगा, जिनमें से प्रत्येक ईरान की विनाशकारी मिसाइलों की सीमा के भीतर आता है, और वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व में ईरान के निर्णय लेने पर उन्हें रोकने की क्षमता या इच्छाशक्ति का अभाव है। इस मामले में भी यही सच है। इनमें से किसी भी देश के पास होर्मुज जैसे जलमार्गों की नाकाबंदी हटाने की शक्ति नहीं है। इसलिए, इन अरबों के लिए ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों को शांत करना सबसे महत्वपूर्ण था। अरबों को पता है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान की बागडोर संभालने का फैसला करता है, तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए कभी ईरान को न्याय के कटघरे में लाने पर अड़े रहने वाले

सऊदी शासक मोहम्मद बिन सलमान ने भी इजरायल के नरसंहार करने वाले प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतृत्वाहू की तरह अब अपनी भाषा बदल ली है। ऐसे में सभी अरब श्रेष्ठ ट्रंप की अजहाम समझौते की नई 'तुरही' से सावधान रहें। उन्हें लगता है कि अगर बिना किसी बातचीत के शांति कागमन हो जाती है तो यह बहुत अच्छा है। न तो शांति समझौते और न ही इसके मसौदा समझौते में दो प्रमुख समस्याएँ शामिल हैं: ईरान का परमाणु विकास कार्यक्रम और जमी हुई ईरानी संपत्ति की रिहाई। नए 60-दिवसीय युद्धविराम में इन दो मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछले युद्धविराम की घोषणा अप्रैल और मई की शुरुआत में की गई थी। जैसा कि ट्रंप अपने 80 वें जन्मदिन के भव्य अवसर पर सौदी की घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे, उनकी सजी हुई प्लेट लेबनान पर इजरायल के हमलों से बिखर गई थी। इसलिए नाराज ट्रंप ने अपने सहयोगी, नरसंहार नेतृत्वाहू को एक लाख गालियाँ दीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चुप रहेगा। इजराइल अभी भी ईरान-अमेरिका समझौते के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ऐसी भूमिका ली गई है। कम से कम दो पिछले मौकों पर जब शांति वार्ता अंतिम चरण में थी, नेतृत्वाहू ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बहाने लेबनान पर आग लगा दी है। इसलिए, ईरान ने तुरंत बातचीत रोक दी। इजराइल ईरान के केन्द्र में होने के साथ पश्चिम एशिया में

स्थायी शांति को स्वीकार नहीं करता है और न ही करेगा। इस बात की संभावना नहीं है कि नेतृत्वाहू अगले 60 दिनों में चुप रहेंगे। ट्रंप हाल ही में नेतृत्वाहू के साथ अक्सर सार्वजनिक रूप से निराश रह रहे हैं; लेकिन नेतृत्वाहू को घेरने की उनकी क्षमता की कमी इस प्रक्रिया में अक्षमता संभावित खतरा है। नेतृत्वाहू का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर है, भले ही अगली राजनीतिक लड़ाई ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन उनके सिंहासन को तुरंत खतरा नहीं है। यह झूलता रहा। यदि यह लड़ाई अरब कम हो रही है, तो यह नरसंहार नेतृत्वाहू के लिए एक अस्तित्वगत मुद्दा बन जाता है। इसलिए, स्थायी शांति या संभावित विनाश की दिशा इस बात पर आधारित होगी कि जानलेवा और भाववह नरसंहार करने वाले आगे क्या करते हैं, न कि पागल ईरानी नेतृत्व और इससे भी अधिक भोले अमेरिकी नेतृत्व पर।

भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने युद्ध या शांति प्रक्रिया में भाग लिए बिना इस अवधि में महत्वपूर्ण हातहतों का सामना किया है। ईरान के साथ हमारी कोई घनिष्ठ मित्रता नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और खाड़ी देशों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जिन्होंने वर्षों से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध विकसित किए हैं, जिनमें से किसी ने भी भारतीय जीवन का गारंटी नहीं दी है या जीवन के नुकसान के लिए माफी नहीं मांगी है। आपने किस राजनयिक को 'बुलाया'

और विरोध किया? चीन या यूरोपीय देशों ने इसे इस तरह व्यक्त किया होगा? ईरान, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती और नवीनतम युद्ध की तीव्रता को बावजूद, हम विश्व मंच पर क्यों बने रहते हैं, यदि लीच नहीं है? पाकिस्तान जैसा बिखरता हुआ देश भी सही समय पर सही तरह की चतुराई दिखाकर ऐसा मोका नहीं छोड़ता। भारत जैसे उभरते, आयात पर निर्भर, उत्पादन-शैशवावस्था वाले देश के लिए विश्व शांति, सभी ईंधन-उर्वरक-औद्योगिक वस्तुओं का अभिसरण, कृषि उपज के लिए बाजार की उपलब्धता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह चेन टूटती है तो यह हजारों आम लोगों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। खड़ी दुनिया का विनाश हो रहा है। उनके उत्थान के लिए अरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए हमें ऐसे संघर्षों के बारे में जागरूक और जागरूक होना चाहिए। इसके बजाय, हम सालगिरह के कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि राजनीतिक हलकों में व्यस्त हैं। जैसा कि ट्रंप, जो रविवार को अस्सी वर्ष के हो गए, वह ईरान युद्ध में शांति लाना चाहते थे, और कुछ घंटों बाद, उन्होंने स्वेच्छा से मसौदा सौदे को मंजूरी दे दी, जो इस सवाल के जवाब छिपाने की कोशिश करेगा कि किसने क्या हासिल किया, क्या खोया, किसने सफलतापूर्वक दलाली की, कौन केवल एक दर्शक था, और इसी तरह। लेकिन यह छिपाना मुश्किल है कि इस युद्ध ने कई लोगों के ज्ञान पर क्या असर डाला है।

डिजिटल होमवर्क का दिखावा और बचपन पर बढ़ता बोझ



- डॉ. सत्यवान सौरभ

शिक्षा वास्तव में आसान हुई है या फिर हम आधुनिकता के नाम पर बच्चों को समय से पहले मोबाइल संस्कृति का हिस्सा बना रहे हैं? पहले विद्यालयों में बच्चे अपनी डायरी में स्वयं गृहकार्य नोट करते थे। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती थी। वे यह सीखते थे कि शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से सुनना, उसे लिखना और समय पर पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब यह जिम्मेदारी बच्चे से हटकर मोबाइल फोन पर स्थानांतरित हो गई है। बच्चा जानता है कि चाहे वह कक्षा में ध्यान दे या न दे, गृहकार्य तो शाम को व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। परिणामस्वरूप उसकी एकाग्रता और उत्तरदायित्व दोनों प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था का दूसरा बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि विद्यालय अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को मोबाइल फोन के उपयोग का अधिकार दे रहे हैं। जब होमवर्क देखने के लिए मोबाइल आवश्यक बना दिया जाता है, तब बच्चे के पास यह तर्क आ जाता है कि उसे पढ़ाई के लिए फोन चाहिए। धीरे-धीरे यही फोन मनोरंजन, गेम, सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियों का माध्यम बन जाता है। जिन अभिभावकों ने अब तक अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा था, वे भी मजबूरी में उन्हें फोन उपलब्ध कराने लगते हैं। भारत जैसे देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहाँ प्रत्येक सदस्य के पास अलग मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है।

कई घरों में एक ही फोन होता है, जिसे परिवार के कमाने वाले सदस्य अपने साथ कार्यस्थल पर ले जाते हैं। ऐसे में यदि स्कूल का गृहकार्य उसी फोन पर भेजा गया हो और फोन घर पर उपलब्ध न हो, तो बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाता है। क्या यह व्यवस्था वास्तव में समावेशी शिक्षा कहलाएगी? शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों तक समान अवसर पहुंचाना है, लेकिन डिजिटल निर्भरता कहीं न कहीं आर्थिक और सामाजिक असमानता को बढ़ा रही है। गर्मी की छुट्टियों का कार्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले छुट्टियों से पहले विद्यालय बच्चों को कार्य-पुस्तिका या लिखित निर्देश दे देते थे। अब कई स्कूल सैकड़ों पन्नों का कार्य व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में भेज देते हैं। अभिभावकों को मजबूरन साइबर कैफे या फोटोस्टेट की दुकानों पर जाकर प्रिंट निकलवाने पड़ते हैं। कई बार इस पर दो सौ, तीन सौ या उससे भी अधिक रुपये खर्च हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि यदि अंततः कार्य कागज पर ही करना है, तो विद्यालय स्वयं वह सामग्री उपलब्ध क्यों नहीं कराते? क्या यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ अभिभावकों पर डालना उचित है? डिजिटल होमवर्क की संस्कृति का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जब बच्चा पढ़ाई के नाम पर बार-बार मोबाइल फोन का उपयोग करता है, तो उसके भीतर स्क्रीन के प्रति आकर्षण बढ़ता है। शोध बताते हैं कि कम उम्र में अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की एकाग्रता,

स्मरण शक्ति और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। विद्यालय जहाँ बच्चों को अनुशासन और संतुलित जीवन शैली सिखाने के केन्द्र माने जाते हैं, वहीं वे स्वयं अनजाने में मोबाइल निर्भरता को बढ़ाते दे रहे हैं। एक अन्य गंभीर समस्या गोपनीयता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। कक्षा के व्हाट्सएप समूहों में अक्सर सभी अभिभावकों के मोबाइल नंबर एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं। कई बार बच्चे बच्चों के समूहों में छात्र-छात्राओं के व्यक्तिगत संपर्क बढ़ने लगते हैं। यह कहना गलत होगा कि हर संपर्क नकारात्मक होता है, लेकिन कम उम्र में अनियंत्रित डिजिटल संवाद बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा सकता है, जिनसे वे मानसिक रूप से निपटने के लिए तैयार नहीं होते। चैटिंग, सोशल मीडिया मित्रता, फैंस पेज पहचान और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में विद्यालयों को केवल तकनीक अपनाने के बजाय उसके सामाजिक प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। विडंबना यह है कि आधुनिकता की इस दौड़ में हम मूल शिक्षा के उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। आज बच्चे तकनीकी उपकरण चलाता तो सीख रहे हैं, लेकिन जीवन कौशल, लेखन क्षमता, आत्म-अनुशासन और व्यवहारिक समझ जैसे गुण अपेक्षाकृत कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हस्तलेखन की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। नोट्स तैयार करने की आदत कम होती जा रही

है। यदि रखने की क्षमता की जगह हूफेन में देख लेगेह वाली मानसिकता विकसित हो रही है। यह भी देखने में आता है कि अनेक विद्यालय डिजिटल माध्यमों को अपनी आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं। अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए मोबाइल एप, ऑनलाइन नोट्स और डिजिटल प्रस्तुतियों को उपलब्ध की तरह प्रवृत्त किया जाता है। लेकिन वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि विद्यालय कितना आधुनिक दिखाता है, बल्कि यह है कि वह बच्चों के सर्वांगीण विकास में कितना योगदान दे रहा है। यदि आधुनिकता बच्चों को मोबाइल पर निर्भर बना रही है, तो उस आधुनिकता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से तकनीक का विरोध नहीं किया जा सकता। तकनीक आज की आवश्यकता है और शिक्षा में उसका महत्वपूर्ण स्थान भी है। लेकिन तकनीक का उपयोग सहायक साधन के रूप में होना चाहिए, विकल्प के रूप में नहीं। यदि किसी दिन डिजिटल माध्यम उपलब्ध न हो, तब भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। विद्यालयों को डायरी लेखन की परंपरा पुनः शुरू करनी चाहिए। गृहकार्य कक्षा में स्पष्ट रूप से बताया और नोट करवाया जाना चाहिए। डिजिटल माध्यम केवल अतिरिक्त सुविधा के रूप में इस्तेमाल किए जाएँ, न कि अनिवार्य माध्यम के रूप में। इसके अलावा विद्यालयों को छुट्टियों के कार्य के लिए मूद्रित सामग्री उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। यदि डिजिटल सामग्री

भेजी भी जाए तो उसके साथ कम खर्च वाले विकल्प भी दिए जाएँ। अभिभावकों और बच्चों की स्क्रीन टाइम के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग सिखाना होना चाहिए, न कि उन्हें तकनीक का गुलाम बनाना। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा में आधुनिकता और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करें। विद्यालयों को यह समझना होगा कि हर परिवार की परिस्थितियाँ समान नहीं होतीं। हर बच्चे के पास व्यक्तिगत मोबाइल उपलब्ध नहीं है। हर अभिभावक डिजिटल संसाधनों का विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जो तकनीक का लाभ भी दे और बच्चों के बचपन, अनुशासन तथा अध्ययन की स्वाभाविक प्रक्रिया को भी सुरक्षित रखे। कोरोना काल की मजबूरी को स्थायी संस्कृति बनाना शिक्षा के हित में नहीं है। यदि हम सचमुच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, तो दिखावटी आधुनिकता से आगे बढ़कर बच्चों की वास्तविक जरूरतों को समझना होगा। अन्यथा हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर देंगे जो उपकरणों को तो अच्छी तरह चलाता जानती होगी, लेकिन आत्मनिर्भर अध्ययन, जिम्मेदारी और जीवन कौशल जैसे मूल गुणों से दूर होती चली जाएगी। शिक्षा का लक्ष्य केवल आधुनिकता बनाना नहीं, बल्कि सक्षम, संस्कारी और संतुलित नागरिक तैयार करना है। यही किसी भी शिक्षण व्यवस्था की वास्तविक सफलता होगी।

गुमनाम पार्टी में क्यों शामिल हुए टीएमसी के नामी सांसद?

तृणमूल कांग्रेस में उठती बगावत ने राष्ट्रीय राजनीति को ऐसा मोड़ दे दिया है जिसकी गूँज आने वाले महिनों तक सुनाई दे सकती है। हम आपको बता दें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 भागी सांसदों ने अचानक एक लगभग गुमनाम दल नेशनलिस्ट सिटिजनस पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग समूह के तौर पर मान्यता तथा सदन में अलग बैठने की मांग कर डाली। इस घटनाक्रम ने केवल बंगाल की राजनीति को नहीं हिलाया, बल्कि दलबदल कानून, विपक्ष की एकजुटता और संसद की शक्ति संतुलन को भी फिर से केन्द्र में ला खड़ा किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस एनसीपीआई में यह विलय हुआ है, उसका अब तक का राजनीतिक अस्तित्व लगभग गमगम रहा है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस दल ने चार उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन

आखिरकार तीन सीटों पर ही चुनाव लड़ पाया। पार्टी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि वे कई जगह नोटा से थोड़ा ही आगे निकल सके। त्रिपुरा की चावमानु सीट पर पार्टी उम्मीदवार बरजेदा त्रिपुरा को केवल 536 वोट मिले, जबकि नोटा को 500 वोट प्राप्त हुए। कैलाशहर सीट पर पार्टी को मात्र 286 वोट मिले। कुल मिलाकर दो सीटों पर एनसीपीआई को सिर्फ 822 वोट हासिल हुए थे। खास बात यह भी है कि इस पार्टी का चुनाव चिह्न हूपेन की निब है और इसने नारा दिया था, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलबदलुओं को नकारें। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि अब वही दल देले के सबसे चर्चित दलबदल का मंच बन गया है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल नाराजगी नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है। भागी सांसदों का मकसद सीधे भाजपा में जाना नहीं, बल्कि पहले एक अलग राजनीतिक पहचान बनाकर दलबदल कानून से बचन माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत यदि किसी दल के दो तिहाई विधायक या सांसद किसी दूसरे दल में विलय करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से राहत मिल सकती है। इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बागी गुट खुद को हूअसली तृणमूल

सर्गाफा व्यापारियों पर मंडराने लगे संकट के बादल, बाजारों में पसरा सन्नाटा

सीजन के समय भी हाथ पर हाथ धरे बैठे व्यापारी, बढ़ते सोना-चांदी के दामों का दिख रहा असर

-राजकुमार सोनी
अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव और बढ़ती महंगाई का असर अब सराफा कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सोना और चांदी के लगातार बढ़ते दामों के कारण बाजारों की रौनक कम हो गई है और व्यापारियों के साथ-साथ कारीगरों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महंगाई के चलते आम उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं। जाचकारों का माना है कि वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर भी बाजारों पर पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और सोनई गैस की कीमतों में वृद्धि ने आम नागरिक की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। सराफा बाजार की वर्तमान स्थिति को लेकर समाजसेवी, पूर्व प्रवक्ता एवं स्वर्णकार विवाह मंच गंजबासोदा के



हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। एक आभूषण के निर्माण में कई कारीगरों का श्रम लगता है और इस उद्योग से बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं। बाजार में बिक्की घटने के कारण कारीगरों को भी पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है। आभूषण निर्माण, माला धाराई, मंगलसूत्र निर्माण तथा अन्य पारंपरिक कार्यों से जुड़े लोगों के सामने भी रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। कई छोटे व्यापारियों को अपनी दुकानें तक बंद करने की नौबत आ गई है। राजकुमार सोनी ने देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि छोटे कारीगरों और सरगाफा व्यापारियों के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जाएँ, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता और रोजगार संधरण मिल सके। उनका कहना है कि सरकार की ओर से उचित सहयोग मिलने पर इस आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यापारी और कारीगर राहत प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो सराफा उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

मानसून करीब होने के बाद भी मनापाई क्रमांक 151 के वत्सलाताई नाइकनगर और श्रमजीवीनगर में नालों की सफाई नहीं



मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुंबई महानगर पालिका जहां एक तरफ मानसून से पहले बड़े नालों की साफ सफाई किए जाने का दावा कर रही है वहीं मनापाई क्रमांक 151 में पड़ने वाली वत्सलाताई नाइकनगर और श्रमजीवीनगर झोपड़पट्टियों में देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कि यहां के प्रमुख नालों की सफाई अभी भी अधूरी है। इस कारण स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई है कि मानसून के दौरान यहां की झुग्गी-झोपड़ियों में बरसाती पानी से जलजमाव होगा। बता दें कि चेंबूर मनापाई पश्चिम विभाग के अंतर्गत आने वाली वत्सलाताई नाइकनगर और श्रमजीवीनगर दोनों ही घनी आबादी झोपड़पट्टियाँ हैं और यहाँ की नालियाँ कचरे, के डेर प्लास्टिक और अन्य कचरे से भरी हुई हैं। अभी तक नालियों की पूरी तरह से सफाई नहीं की गई है। जिसके कारण बरसात का पानी बस्तियों में जमा होने की संभावना है। इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए गत दिनों मुंबई कांग्रेस एस. सी. सेल के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भलेराव ने दोनों नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नालों की सफाई के काम को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और मनापाई तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों पर निशाना चलाया। उन्होंने कहा कि मानसून करीब होने के बावजूद नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई। भालेराव ने कहा कि नालों की सफाई पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नालों में गाद और कचरा अभी भी जमा पड़ा है।

भाजपा बोर्डसर मंडल सचिव पद पर जूली बारी की नियुक्ति



पालघर(उत्तरशक्ति)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बोर्डसर मंडल कार्यकारिणी में जूली संजय बारी को सचिव पद पर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। भाजपा बोर्डसर मंडल अध्यक्ष महेंद्र भोगे के द्वारा हस्ताक्षर युक्त जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि जूली बारी की पार्टी के प्रति निष्ठा, ईमानदार कार्यशैली तथा समाजसेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के मार्गदर्शन तथा पालघर जिला अध्यक्ष भरतभाई राजपूत के नेतृत्व में की गई है। नियुक्ति पत्र में विश्वास व्यक्त किया गया है कि जूली बारी पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित रहकर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा आम जनता से पार्टी का संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई है कि उनके नेतृत्व में मंडल स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और भाजपा की जनगण मजबूत करने की मुहिम को बल मिलेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने भी जूली बारी की नियुक्ति का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी है।

मनबा फाइनेंस का दक्षिण भारतीय बाजार में प्रवेश

मुंबई। मनबा फाइनेंस लिमिटेड, भारत की एक प्रसिद्ध क्लिक-फाइनेंसिंग NBFC, ने आज श्रीरस्था (नन्मा लोन) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी के जरिए दक्षिण भारतीय बाजार में प्रवेश करने की घोषणा की। यह साझेदारी देश में मनबा के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो आने वाले समय में दक्षिण भारत के सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से कंपनी के विस्तार की नींव बनेगी। इस वित्तीय वर्ष में, कर्नाटक में विस्तार के जरिए इस सहयोग की शुरुआत होगी, जिसके बाद तमिलनाडु में काम शुरू होगा। उसके बाद दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी चरणबद्ध तरीके से विस्तार की योजना है। इस पहल के अंतर्गत, दक्षिण भारत में 100 से अधिक संभावित स्थानों की पहचान की गई है। कंपनी बाजार की तैयारियों और परिचालनात्मक प्रारंभिकताओं के अनुसार धीरे-धीरे इन स्थानों में परिचालन आरम्भ करेगी। इस साझेदारी के पीछे की गहरी विशेषज्ञता ही इस सहयोग की खासियत है। चार वरिष्ठ लीडर्स की एक कोर टीम इस उद्यम का नेतृत्व कर रही है, जो वाहन ऋण उद्योग में संयुक्त रूप से 100 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। वाहनों की उत्पत्ति, ऋण, संग्रह और वाहन-ऋण मूल्य श्रृंखला में जमीनी स्तर पर वितरण जैसे सभी पहलु इनकी कार्य श्रेणी का हिस्सा हैं।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने 'इंडियन आइडल' के मंच पर एक साथ गाया 'छैया छैया'

मुंबई/पटना। 'इंडियन आइडल' का आगामी एपिसोड एक बेहद ऐतिहासिक और यादगार पल का गवाह बनने जा रहा है। संगीत जगत की दो दिग्गज हस्तियाँ, सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी, भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार एक साथ मंच पर बॉलीवुड के सबसे बड़े डांस एंथम 'छैया छैया' को लाइव परफॉर्म करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। एपिसोड के दौरान, जज बादशाह ने बॉलीवुड के इस सबसे आइकॉनिक गाने से जुड़ा एक दिलचस्प सच साझा करते हुए कहा, आप दोनों का एक गाना है जो बेहद लेजेंड्री और आइकॉनिक है, जिस पर हमारी जनरेशन तो पागल होकर नाची ही है, हमसे पहले वाली भी और हमसे बाद वाली भी, और पूरी दुनिया भर में। सर, यह गाना इतना आइकॉनिक है कि इसकी रीच की कोई सीमा नहीं है। पर मैंने सुना है कि यह गाना आप लोगों ने अलग-अलग रिकॉर्ड किया था और यह गाना हमने कभी आप दोनों को एक साथ परफॉर्म करते हुए भी नहीं देखा है। मुझे ऐसा लगा कि आज अगर आप दोनों यहाँ पर हैं, तो वो हो जाना चाहिए।

बादशाह ने आगे कहा, आज तक ऐसा कोई शो नहीं है, कोई सिंगिंग या डांस रिकॉमिनिशन नहीं है जहाँ पर यह गाना न बजा हो और इस गाने ने शो की रेटिंग्स न बढ़ा दी हों। लेकिन आज तक ऐसा कोई शो, इवेंट या अवॉर्ड फंक्शन भी नहीं हुआ है जहाँ पर इन दोनों को एक साथ गाते देखा गया हो। अगर आप ऐसा करने के लिए हाँ कह देते हैं, तो प्लीज कीजिए।

जिला बैंक चुनाव में महायुति समर्थित परिवर्तन पैलल मैदान में, हमारे साथ पार्टी की पूरी ताकत : कपिल पाटिल

आचार्य सुरजपाल यादव भिवंडी (उत्तरशक्ति)। ठाणे-पालघर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। महायुति समर्थित परिवर्तन पैलल के प्रमुख एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कपिल पाटिल ने दावा किया है कि उनकी पैलल के पीछे भाजपा और महायुति नेतृत्व की पूरी ताकत खड़ी है तथा विरोधी खेमे में बेचेनी बढ़ गई है। पत्रकारों से बातचीत में कपिल पाटिल ने कहा कि राजनीति में चुनाव के दौरान प्रतिद्वंद्वी अक्सर मजबूत शक्ति केंद्रों को निशाना बनाते हैं। परिवर्तन पैलल के मजबूत खेमे से विरोधियों के पांव तले जमीन हिसक गई है, इसलिए जिला बैंक चुनाव के माध्यम

से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण जैसे शक्ति केंद्र पर राजनीतिक हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिवर्तन पैलल के उम्मीदवारों का चयन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालघर के पालकमंत्री गोपाई नाईक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से चर्चा के बाद किया गया है। इसके बावजूद उनके राजनीतिक विरोधी विधायक किशन कथारे ने शिवसेना, बहुजन विकास आघाड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) को साथ लेकर सहकार पैलल के माध्यम से चुनौती खड़ी की है। कपिल पाटिल ने आरोप लगाया कि भाजपा के ही एक नेता ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के निदेशों की



अनदेखी कर सहकार पैलल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल लांडगे के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हुई थी और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सहमति के बाद परिवर्तन पैलल में भाजपा को चार तथा शिवसेना को तीन सीटें दी गईं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि

सहकार पैलल की पत्रकार परिषद में परिवर्तन पैलल के शिवसेना उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान की अपील नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें भी अपना ही साथी बताया गया था। कपिल पाटिल ने कहा कि सहकार पैलल में भाजपा और शिवसेना को केवल एक-एक सीट मिली है, जबकि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण का समर्थन परिवर्तन पैलल के साथ है, इसलिए यह वास्तविक भाजपा समर्थित पैलल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बैंक के मतदाता परिवर्तन पैलल को समर्थन देकर सत्ता की बागडोर सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि परिवर्तन पैलल के गठन के बाद विरोधी खेमे में चकराहट है और उनके पांव तले की जमीन खिसक चुकी है।

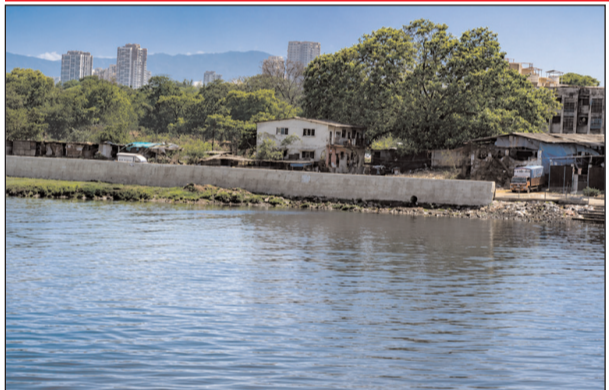
इसजु मोटर्स इंडिया ने देशभर में आई-केयर प्री-मानसून सर्विस कैंप की शुरुआत की

मुंबई। इसजु अपने ग्राहकों को बेमिसाल सेवाएं उपलब्ध कराने और वाहनों के मालिक के तौर पर उन्हें बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के अपने वादे पर कायम है। अपने इसी वादे को और ज्यादा मजबूत करते हुए, इसजु मोटर्स इंडिया की ओर से अपने इसजु डी-मैक्स पिक-अप और एसयूवी रेंज के लिए देश भर में इसजु आई-केयर प्री-मानसून कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस सर्विस कैंप का उद्देश्य ग्राहकों को आकर्षक फायदों के साथ-साथ रखरखाव के लिए एहतियाती जाँच की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि पूरे देश में सभी ग्राहकों को इस मौसम में बिना परेशानी के शानदार ड्राइविंग का अनुभव मिल सके। इसजु कैंप की इस पहल के तहत, 18 से 24 जून, 2026 (दोनों दिन शामिल है) के बीच देश भर में इसजु के सभी अधिकृत डीलर

सर्विस आउटलेट्स पर प्री-मॉनसून कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ग्राहक अपने वाहनों के लिए खास ऑफर्स के साथ-साथ शानदार फायदों का भी आनंद ले सकते हैं। कैंप में आने वाले ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएँ मिलेंगी: - मुफ्त में वाहन के 37 पॉइंट्स की पूरी जाँच। लेबर चार्ज पर 10% की छूट। पाटर्स पर 5% की छूट। ल्यूब और फ्लूइड पर 5% की छूट। रिटेल पर आ सेवाओं पर 20% की छूट। आगरा, अहिल्यानगर, अहमदाबाद, अंबिकापुर, अनंतपुर, बारामूला, बरेली, बाडमेर, भरुक, बठिंडा, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, बिलासपुर, कालीकट, छत्रपति संभाजी नगर, चेन्नई, चिक्कमंगलूर, कोयंबटूर, धुले, दिल्ली, डिब्रूगढ़, दोमापुर, दुर्गापुर, एनाकुलम, गांधीधाम, गोरखपुर, आदि।

खड़ी में रिटेनिंग वॉल निर्माण को लेकर उठा विवाद

बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका: अकिल अंसारी



कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण (पश्चिम) क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल (दीवार) के निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है। खाड़ी किनारे चल रहे इस निर्माण

संबंधित क्षेत्र में बिना पर्याप्त योजना के रिटेनिंग वॉल का काम शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस निर्माण का सीधा असर बारिश के मौसम में देखने को मिल सकता है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना बढ़ जाएगी। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि संभावित बाढ़ जैसी स्थिति को टालने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही, पूरे मामले की जांच कर उचित उपाय योजना लागू करने की अपील भी की गई है। इस संबंध में प्रशासन से विस्तृत जानकारी लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग उठ रही है, ताकि आने वाले मानसून में किसी भी तरह की आपदा से बचा जा सके।

विवेकानंद कॉलेज में शुरु हुआ एबीवीपी का तीन दिवसीय अभ्यास वर्ग



मुंबई (उत्तरशक्ति)। चेंबूर स्थित स्वामी विवेकानंद कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का तीन दिवसीय अभ्यास वर्ग 15 जून से शुरू हो गया। इस प्रशिक्षण एवं वैचारिक सत्र में संगठन के विभिन्न पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अभ्यास वर्ग के उद्घाटन

वर्ग में बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विशेष रूप से 15 वर्षीय युवाध्याय सबसे कम उम्र के सहभागी के रूप में आकर्षण का केंद्र रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास वर्गों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक कौशल को मजबूत करना है, ताकि विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें। तीन दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग में विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन सत्र, विचार-विमर्श और संगठनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

पालघर में स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत, 31 जुलाई तक चलेगा जनजागरूकता अभियान



आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अतिसार से पीड़ित प्रत्येक बच्चे को तत्काल ओआरएस घोल और जिंक की गोलियां उपलब्ध कराई जायेंगी तथा उनके सही उपयोग की जानकारी अभिभावकों को दी जायेगी। साथ ही घर-घर संपर्क, ग्राम सभाएं, स्कूल एवं आंगनवाड़ी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, हाथ धोने की आदत, स्तनपान व पूरक आहार के महत्व पर भी विशेष जोर दिया जायेगा। जिले में लगभग 1 लाख 56 हजार 283 पांच वर्ष

से कम आयु के बच्चों तक इस अभियान का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए आशा स्वयंसेविकाएं, आंगनवाड़ी सेविकाएं, स्वास्थ्य कर्मचारी तथा विभिन्न स्तरों के अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। जिला माता एवं बाल संगोपन अधिकारी डॉ. वैदेही मालवी ने कहा कि बच्चों में अतिसार के लक्षण दिखाई देने पर अभिभावक तुरंत निकटतम शासकीय स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। उन्होंने सलाह दी कि अतिसार होने पर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ, ओआरएस घोल और चिकित्सक की सलाह के अनुसार जिंक की गोलियां दें, स्तनपान जारी रखें तथा निर्जलीकरण के लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी ने नागरिकों से स्वच्छता की आदतें अपनाने, सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने तथा हार्स्टॉप डायरियाहू अभियान में सक्रिय भागीदारी कर बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

मिठंडी मनापा ने 9वीं-10वीं के 2815 विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने से विद्यार्थियों में उत्साह

मुंबई। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों की शैक्षणिक नींव मजबूत करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिठंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका ने महत्वपूर्ण छत्रहितैषी निर्णय लिया है जिसमें विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मुहैया करायेगी। मनापा के इस फैसले से विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल बनेगा। मनापा के इस महत्वाकांक्षी फैसले का अर्थ है कि मनापा की शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 9वीं और 10वीं के लगभग 2815 विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। मनापा महानगरपालिका ने महत्वाकांक्षी फैसले का अर्थ है कि मनापा की शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 9वीं और 10वीं के लगभग 2815 विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। मनापा महानगरपालिका ने महत्वाकांक्षी फैसले का अर्थ है कि मनापा की शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 9वीं और 10वीं के लगभग 2815 विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। मनापा महानगरपालिका ने महत्वाकांक्षी फैसले का अर्थ है कि मनापा की शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 9वीं और 10वीं के लगभग 2815 विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस योजना के लिए मनापा ने अपने बजट में बर्खास्त ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष प्रावधान करते हुए 1 करोड़ रुपये का निधि आरक्षित किया था। इसी निधि से विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई यह महत्वाकांक्षी योजना अब सीधे उनके हित में उपयोग की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाठ्यपुस्तकों की खरीद शासकीय भंडार गृह के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्माता एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल (बालभारती) से की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, अद्यतन एवं गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध होंगी। मनापा ने स्पष्ट किया है कि पुस्तक खरीद प्रक्रिया में किसी भी निजी विक्रेता, एजेंट या

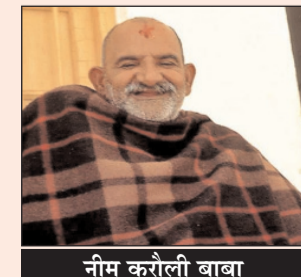
विचौलिया की भागीदारी नहीं होगी। संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, नियमबद्ध और सरकारी प्रक्रिया के अनुसार संपन्न की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों तक प्रमाणित और अधिकृत पाठ्यपुस्तकें पहुंच सकें। इस योजना का लाभ केवल मिठंडी निजामपुर मनापा की शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही विद्यार्थियों के हाथों में पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के उपआयुक्त बालकृष्ण शौरसागर तथा प्रशासन अधिकारी सौदागर शिखरे ने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने तथा स्कूल छोड़ने की दर कम करने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी और हजारों विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को नई दिशा देगी।

हीरो फिनकोर्प ने एजेंटफोर्स की मदद से लोन प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए सेल्सफोर्स के साथ साझेदारी की

मुंबई। नंबर 1 एजेंटिक सीआरएम, सेल्सफोर्स ने आज डाईवर्सिफाइड भारतीय एन.बी.एफ.सी. हीरो फिनकोर्प के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी का उद्देश्य एजेंटफोर्स की मदद से लोन प्रोसेसिंग में तेजी लाना है। हीरो फिनकोर्प के साथ इस साझेदारी द्वारा लॉन्डिंग प्रक्रिया के मुख्य चरण स्ट्रीमलाइन हुए हैं, जिससे फस्ट-टाइम खरीददारों के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने में तेजी आई है, जिसमें डॉक्यूमेंट निकासन, एप्लीकेशन का सत्यापन करना, पैन और आधार वैरिफिकेशन, क्रेडिट एवं बैंक चेक, ई-सिग्नेचर शुरू करना, डॉक्यूमेंट और लोन का वितरण शामिल है। इससे व्यापक स्तर पर ज्यादा तेज और प्रभावशाली लॉन्डिंग संभव होती है। डेटा 360 सेल्सफोर्स और बाहरी

डेटा स्रोतों को संगठित करता है और ऑटोमेशन के लिए एप्लिकेशन आधार बनाता है। म्यूल्सॉफ्ट, एपीआई-आधारित इंटीग्रेशन द्वारा सरकारी सत्यापन सिस्टम, फाइनेंशियल संस्थानों और डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी को कनेक्ट करता है। एजेंटफोर्स सेल्स और एजेंटफोर्स सर्विस लोन देने की प्रक्रिया में कस्टमर एवं ऑपरेशनल वर्कफ्लो को सुगम बनाते हैं। इन सभी क्षमताओं को मिलाकर लोन अनुमोदन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन होती है और कस्टमर सैटिस्फेक्शन एवं टीम की प्रोडक्टिविटी में ठोस सुधार हुए हैं। हीरो फिनकोर्प ने एजेंटफोर्स, डेटा 360, म्यूल्सॉफ्ट, एजेंटफोर्स सेल्स और एजेंटफोर्स सर्विस की मदद से इंटीग्रेजेटेड लोन प्रोसेसिंग के लिए कनेक्टेड बुनियाद स्थापित की है। एजेंटफोर्स हीरो फिनकोर्प में प्रि-सेक्शन और पोस्ट-सेक्शन टास्क को ऑटोमेट करता है, जिसमें डॉक्यूमेंट निकासन, एप्लीकेशन का सत्यापन करना, पैन और आधार वैरिफिकेशन, क्रेडिट एवं बैंक चेक, ई-सिग्नेचर शुरू करना, डॉक्यूमेंट और लोन का वितरण शामिल है। इससे व्यापक स्तर पर ज्यादा तेज और प्रभावशाली लॉन्डिंग संभव होती है। डेटा 360 सेल्सफोर्स और बाहरी

बढ़ती मांग को ज्यादा फुर्ती से पूरा करने में मदद मिली है। कंपनी ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं दे पा रही है, डीलर के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं और भारत में क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ रही है। श्री अभिमन्यु मुंजल, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, हीरो फिनकोर्प ने कहा, हीरो फिनकोर्प में हम ए.आई, डेटा और डिजिटल इनोवेशन की मदद से क्रेडिट प्राप्त करने का तरीका बदल रहे हैं। भारत में हमारे बिजनेस के विस्तार और बढ़ते वित्तीय समावेशन के साथ हम टेक्नोलॉजी और कस्टमर अनुभव में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। सेल्सफोर्स के साथ हमारी साझेदारी हमारे इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। इससे लॉन्डिंग की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन होगी और टर्नअराउंड टाइम में काफी कमी आएगी।



नीम करौली बाब

उत्तरशक्ति

* संपादक: ओमप्रकाश प्रजापति

* उप संपादक: प्रेम चंद मिश्रा

* प्रबंध संपादक: डा. शेषधर बिन्द

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पत्राचार कार्यालय :

उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)

मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्ल्यू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जबल ऑटफ हिल वडला, मुंबई-37

मो.- 9554493941

email ID- uttarshaktinews@gmail.com

प्रजापति

फॅब्रीकेशन अॅण्ड गिलवर्क्स

PRAJAPATI

FABRICATION & GRILL WORKS

MANUFACTURERS OF

COMPOUND GATES, MS GRILLS, WATER TANKS, ROLL SHUTTER, COLLAPSIBLE DOOR & ALUMINIUM SLIDING WINDOW

SHOP NO. 101, SAVERA CHS. LAST BUS STOP VEERA DESAI ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI-400053. GST No. : 27ANKPP6297R1ZP

93245 26742
98200 55193
93227 55403

भारतीय नाविकों की मौत पर सपा नेता अरशद खान ने उठाए सवाल, निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में भारतीय नाविकों की कथित मौत पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

अरशद खान ने कहा कि भारतीय नाविकों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ऐसे मामलों में सरकार को दृढ़ता और स्पष्टता के साथ पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय नागरिकों की जान गई है तो इस घटना की निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच कराई जानी



चाहिए तथा जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु और स्वाभिमानी राष्ट्र है तथा राष्ट्रीय हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश की जनता यह जानना चाहती है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की

पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है। सपा नेता ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार और देशभक्ति का हिस्सा है। इसलिए केंद्र सरकार को संसद और देश के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए तथा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

अरशद खान ने मृतक नाविकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा देश इस दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से पीड़ित परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता और हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा मजबूती से उठाने की भी अपील की।

व्यापारियों की समस्याओं का किया जाय समाधान: आरिफ हबीब

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री/पूर्व सांसद बनवारी लाल कच्छल के निर्देश पर

जापान में मांग की गई कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए तथा दुकानों में आगजनी जैसी घटनाओं



रीडिंग के आधार पर बिलिंग होने के कारण फिक्स चार्ज एवं न्यूनतम चार्ज समाप्त करने की भी मांग उठाई गई। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की मांग भी जापान में शामिल रही।

जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान करेगी। इस अवसर पर जिला महामंत्री आरिफ हबीब खान, नगर अध्यक्ष धनश्याम साहू तथा प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष इन्द्रमन सिंह इन्दु के हस्ताक्षरयुक्त जापान कल 15 जून को शाम साढ़े 7 बजे प्रस्तुत किया गया। जापान देने वालों में जिला कोषाध्यक्ष उमेशचंद्र गुप्त, नगर महामंत्री आलोक रंजन सिन्हा, युवा जिला अध्यक्ष अरुण शुक्ल, युवा जिला उपाध्यक्ष सुमित कुमार प्रमुख रूप से रहे। उक्त आशय की सूचना जिला महामंत्री आरिफ हबीब ने दी है।

से सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपये तक का बीमा उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही विभागीय बकाया अथवा रिटर्न देर से जमा करने पर लगने वाले 18 प्रतिशत ब्याज को घटकर 9 प्रतिशत किए जाने की मांग रखी गई।

व्यापार मंडल ने यह भी मांग की कि विभिन्न विभागों के लाइसेंस आजीवन बनाए जाएं और व्यापारियों पर होने वाले सवें व छठों को कानून सम्मत तरीके से संचालित किया जाए। बिजली बिल में मीटर

मुहर्रम को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु बैठक आयोजित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को देर सायं आगामी मुहर्रम को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने हेतु बैठक सम्पन्न हुई।

स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा एम्बुलेंस, एम्बुएसी, पीएचसी एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को पूर्ण रूप से तैयार रखा जाए।



विद्युत विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड में कार्य करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग और एक्स ई एन जल निगम को जुलूस मार्गों की सड़कों की मरम्मत एवं आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने तथा नगर निकायों को साफ-सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि जुलूसों में स्वयंसेवकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए तथा नेहरू युवा केंद्र एवं सिविल डिपेंस के स्वयंसेवकों की सहभागिता भी सुनिश्चित कराई

जाए। साथ ही तहसील के अधिकारियों को सतर्क रहने तथा तैयारी पूर्ण कर ली गयी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की नई परंपरा प्रारंभ नहीं की जाएगी तथा ताजियों की ऊंचाई एवं चौड़ाई निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूचना अथवा समस्या के लिए पुलिस एवं प्रशासन 24 घंटे उपलब्ध है। इस दौरान पर्याप्त पुलिस बल को तैनाती की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखते हुए आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक आलुप श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) अजय अंबेड, नगर मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह सहित शांति समिति के सदस्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

हत्यारोपी पति सहित तीन को आजीवन कारावास

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्धदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार आजमगढ़ निवासी अब्दुल रईस ने खेतासराय में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी बहन अंजुम का निकाह मवाई गांव के इमरान के साथ 31 दिसंबर 2017 को हुआ था। उपहार में काफ़ी सामान दिया गया था किंतु मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति इमरान सास रेहाना तथा नन्द मल्लिका व साबिरा तथा पड़ोस की चुन्नी पत्नी सिराज उसे मारती पीटती थी। 13 मई 2018 को दिन में 3 बजे यह लोग अंजुम को मार पीटकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने पति इमरान सास रेहाना को दहेज हत्या में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपए अर्धदंड से दंडित किया जबकि पड़ोसन चुन्नी को हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्धदंड से दंडित किया।

पॉपिंग सेट चालू करते समय करंट की चपेट में आए युवक की मौत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जलालपुर थाना क्षेत्र के सिरकोनी गहल गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी लव यादव (40 वर्ष) खेत में पॉपिंग सेट चालू कर रहे थे, तभी अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गए। परिजनों और ग्रामीणों ने गंभीर अवस्था में उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। हालांकि हादसत अत्यंत गंभीर होने के कारण उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है तथा गांव में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खेत में मिट्टी डालने के विवाद में हुई मारपीट, बुजुर्ग की मौत, 4 आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत थाना क्षेत्र के ग्राम धरौरा में खेत में मिट्टी डालने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार, गांव के दो पड़ोसी परिवार, जो आपस में पट्टीदार भी हैं, के बीच सोमवार को कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान रामदुलार सरोज (65 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतक के परिजनों की तहरीर ने आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा शीघ्र ही एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। पुलिस के अनुसार, घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कवि जितेन्द्र कुमार दुबे से डॉ.रश्मिशील की शिष्टाचार भेंट

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। हजरतगंज स्थित कार्यालय में जवाहर भवन की व्यवस्था अधिकारी डॉ. रश्मिशील ने अपर पुलिस उपायुक्त मध्य एवं सुप्रसिद्ध कवि जितेन्द्र कुमार दुबे से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर शोधार्थी अश्वनी तिवारी की उपस्थिति में उन्होंने सेवानिवृत्त आईएसएस अधिकारी एवं साहित्यकार जायशंकर मिश्र की काव्ययात्रा पर आधारित पुस्तक 'कुछ चित्र रचे-कुछ रंग भरे' भेंट की। भेंट के दौरान साहित्य, संस्कृति एवं समासमयिक विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। ज्ञातव्य है कि कवि जितेन्द्र कुमार दुबे की कविताएँ विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। साहित्य और प्रशासन, दोनों क्षेत्रों में उनकी सक्रिय उपस्थिति उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।

रास्ते के विवाद में बुजुर्ग की राड से पीटकर हत्या

चार आरोपी लिये गये हिरासत में, धरौरा गांव में तनाव का माहौल केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के धरौरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर देर रात एक बुजुर्ग की लोहे की राड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया। जिसके चलते कई थोनों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी भी रात में मौके पर पहुंचे।

रास्ते को लेकर हुआ था विवाद: मृतक की पहचान 68 वर्षीय रामदुलार सरोज के रूप में हुई है। आरोप है कि जब रामदुलार रात में अपने घर में सो रहे थे, तभी उनके पटीदारों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। लोहे की राड से किए गए हमले के कारण रामदुलार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र लोहा सरोज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके परिवार के ही लोग घर का निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान रास्ते को लेकर विवाद शुरू हो गया था। शाम को ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो रही थी। रामदुलार सोने चले गए। जिसके बाद आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

सभी नाम जद आरोपी पुलिस हिरासत में: लोहा सरोज की तहरीर पर पुलिस ने सती, शुभम, अमरेश, और कृष्ण सहित चार नामजद लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मेडिकल कॉलेज जौनपुर में जटिल शल्य चिकित्सा की बड़ी सफलता, चिकित्सकों की तत्परता से मरीज को मिला नया जीवन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उमानाथ सिंह स्वशास्री राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर ने एक बार फिर उकृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय देते हुए एक जटिल शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में गंभीर अवस्था में भती एक मरीज का चिकित्सकों की कुशलता, त्वरित निर्णय क्षमता तथा समर्पित टीमवर्क के बल पर सफल ऑपरेशन कर उसे राहत प्रदान की गई।

(डॉ॰) ए॰ए॰ जाफरी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं उनके विभाग के चिकित्सक डा॰ हिमांशु सिंह, डा॰ राजन्य प्रजापति तथा नर्सिंग एवं सहायक स्टाफ- अंजुन, उपामान, इन्दु, मीना, आस्था, प्रेम, जुबेर, अभिषेक, विशाल, शिवम एवं सुनील के महत्वपूर्ण भूमिका का परिणाम रहा। इस जटिल शल्य चिकित्सा में एंस्थीसिया प्रदान करने में डॉ॰ आदर्श यादव का विशेष योगदान रहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहगंज, जनपद जौनपुर निवासी एक 24 वर्षीय मरीज को पेशाब में अत्यधिक जलन, रुक-रुक कर मूत्र आने तथा तीव्र असहजता की शिकायत के कारण मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों द्वारा तत्काल आवश्यक जांचें कराए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि मरीज के मूत्राशय (यूरिनेरी ब्लैडर) एवं मूत्रमार्ग में पथरी फंसी हुई है, जिसके कारण उसकी स्थिति लगातार जटिल होती जा रही थी। मरीज की गंभीरता को देखते हुए तत्काल शल्य चिकित्सा की निर्णय लिया गया। बिना समय गंवाए आधुनिक तकनीक एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से इमरजेंसी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान वफरछ (यूरोट्रोस्कोपिक लिथोटॉमी) एवं उख स्टैंटिंग तकनीक का सफल प्रयोग करते हुए मरीज के मूत्रमार्ग तथा मूत्राशय से लगभग 15 मिमी का एक कठोर पथरी को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। पूरी प्रक्रिया अत्यंत सावधानी एवं दक्षता के साथ सम्पन्न की गई, जिससे मरीज को तत्काल राहत मिली। यह सफलता सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो॰



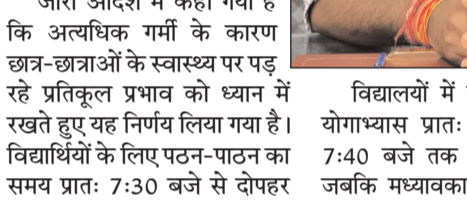
वर्तमान में मरीज पूर्णतः स्वस्थ है तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में तेजी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है। मरीज एवं उसके परिजनों ने मेडिकल कॉलेज की त्वरित चिकित्सा व्यवस्था आधुनिक सुविधाओं तथा चिकित्सकों के समर्पित प्रयासों का सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। इस महत्वपूर्ण सफलता पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो॰ (डा॰) आर॰ बी॰ कमल ने पूरी सर्जरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान का उद्देश्य प्रत्येक मरीज को समयबद्ध, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जौनपुर के चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी निरंतर जनसेवा के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं तथा अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से पूर्णचल के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यह सफलता मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ चिकित्सा क्षमता, आधुनिक संसाधनों तथा टीम भावना का उकृष्ट उदाहरण है, जो जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए आशा और विश्वास का केंद्र बनती जा रही है।

भीषण गर्मी के चलते जौनपुर के परिषदीय विद्यालयों का समय बदला

सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी कक्षाएं

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी परिषदीय विद्यालयों के संचालन समय में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार 16 जून 2026 से जिले के सभी परिषदीय विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे।

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद में 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों एवं संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संशोधित समय-सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिल सके और शिक्षण कार्य भी सुचारु रूप से संचालित होता रहे।

जिला उपाध्यक्ष डाक्टर सन्तोष कुमार गिरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। राहुल गांधी के आह्वान पर चलाए जा रहे ग्रेट निकोबार द्वीप बचाओ हस्ताक्षर अभियान को केराकत चौराहा के समीप जौनपुर गाजीपुर मार्ग पर स्थित ब्लाक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में लोगों का व्यापक जनसम्मेलन मिला। अभियान के तहत केराकत तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में जनसम्मर्क व हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित कर केराकत वासियों व ग्रामीणों को ग्रेट निकोबार के पर्यावरणीय महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डाक्टर सन्तोष कुमार गिरी प्रभारी केराकत व जफराबाद के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जौनपुर व प्रभारी केराकत, जफराबाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डाक्टर सन्तोष कुमार गिरी ने कहा कि ग्रेट निकोबार केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता व पर्यावरणीय संतुलन का अहम केन्द्र है। इसे कापोरेंट लुट से बचाने की जरूरत है। बड़ी संख्या में हस्ताक्षर कर अभियान को समर्थन दिया है।

जिला उपाध्यक्ष डाक्टर सन्तोष कुमार गिरी ने आगे कहा कि ग्रेट निकोबार को कापोरेंट हत्यों की भेंट चढ़ाने की किसी भी कोशिश का कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जन - जन जागरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस मौके पर जिला सचिव आशीष यादव, ब्लॉक अध्यक्ष केराकत नरेन्द्र प्रताप, सुशील सोनकर, अध्यक्ष डोभी सुभाष सिंह, वकील अन्सारी, नगर अध्यक्ष केराकत मोहम्मद नसीम, नन्हें डाक्टर सुजीत पाल, बासदेव यादव आदि कांग्रेसी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

जौनपुर के दामाद प्रो. एस.पी. सिंह बने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारत सरकार ने शिक्षाविद प्रो. एस. पी. सिंह को गुजरात के आनंद स्थित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) का प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जौनपुर स्थित उनके ससुराल पक्ष और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रो. एस. पी. सिंह का विवाह वर्ष 1999 में जौनपुर के जमालपुर निवासी एवं सेवानिवृत्त डायरेक्टर मेडिकल शिक्षा स्वर्गीय डॉ. रणविजय सिंह की पुत्री सारिका सिंह से हुआ था। वर्तमान में उनका ससुराल परिवार शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे के निकट निवास करता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रो. सिंह ने अपने शैक्षणिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने प्रवक्ता, आचार्य, निदेशक और कुलपति के रूप में विभिन्न संस्थानों में सेवाएं दी हैं। वर्ष 2001 में वे गुवाहाटी स्थित रॉयल गुप्त ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक निदेशक बने। बाद में एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और कोशल्या द स्कूल यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2025 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह विश्वविद्यालय सहकारी प्रबंधन, ग्रामीण विकास और कृषि-व्यवसाय संबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रो. एस. पी. सिंह की इस महत्वपूर्ण नियुक्ति को जौनपुर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उनके कुलपति बनने पर परिजनों, मित्रों, शिक्षाविदों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है।

जौनपुर का सरपतहां पुलिस थाना जनपद की शान

शिव पूजन पाण्डेय जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश के 1526 थानों में अब जौनपुर का सरपतहां थाना खूबसूरती और व्यवस्था के लिए अलग पहचान बना रहा है। 1902 में स्थापित इस थाने की 123 साल पुरानी इमारत को जस का तस रखते हुए कायाकल्प कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से 55 किमी दूर सुल्तानपुर सीमा से सटे वीरान इलाके में स्थित इस थाने को कभी कोई पुलिसकर्मी पोस्टिंग नहीं चाहता था, पर आज यही थाना जिले में सुंदरता के मामले में पहले नंबर पर गिना जा रहा है। थाना प्रभारी यजुवेंद्र सिंह की सोच और लगन ने इस बदलाव की नींव रखी। सबसे बड़ी चुनौती वीरानगी थी। थाने से एक किमी दूर तक चाय की दुकान तक नहीं थी। रोजमर्रा का सामान लेने कर्मियों को रूथली बाजार जाना पड़ता था। इस दिक्कत को देखते हुए थाना परिसर में ही कंटीन बना दिया गया है। यहां चाय-नाश्ता से लेकर जरूरत का हर सामान उचित मूल्य पर मिलता है। परिसर के भीतर अब हरा-भरा माहौल है। तुलसी वाटिका, भव्य मंदिर और फव्वारे से आंगन सज गया है। जवानों के लिए बॉलीबॉल मैदान और बैथिंग्टन कोर्ट बनाया गए हैं ताकि ड्यूटी के बाद तनाव हल्का हो सके। मुंशी कार्यालय और सीसीटीव्ही कक्ष को पूरी तरह वतानुकूलित किया गया है। भोजनालय की व्यवस्था

कर्मियों को सबसे बड़ी राहत दी है। मात्र 32 रूपए में भरपेट शाकाहारी भोजन मिलता है। हफ्ते में दो दिन पनीर, एक दिन खीर और एक दिन चावल की जगह पुलाव परोसा जाता है। मांसधातु कर्मियों के लिए हफ्ते में एक दिन अंडा करी और एक दिन चिकन या मटन की व्यवस्था है। साफ-सफाई और समय पर भोजन से सभी के चेहरे पर खुशी दिखती है। बुनियादी सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है। पूरे थाने को 24 घंटे बिजली-पानी उपलब्ध है। आवासीय भवन स्वच्छ रखे गए हैं और पूरा परिसर अब सोलर पैनल पर निर्भर हो चुका है। इससे बिजली का खर्च भी बचा और पर्यावरण को सहयोग भी गया। थाना प्रभारी यजुवेंद्र सिंह मानते हैं कि ये बदलाव अकेले संभव नहीं था। इसमें दीवान संजीव सिंह, सिपाही अश्विन राय, पथन यादव और शरद वैश्य की भूमिका अहम रही। स्थानीय जनता के सहयोग से अनुभवीदात्री से यह मॉडल खड़ा हुआ है। आज सरपतहां थाना सिर्फ कानून-व्यवस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। जहां पहले पोस्टिंग से लोग बचते थे, वहां आज तैनाती की इच्छा जताई जा रही है। 1902 की विरासत को बचाते हुए 2026 का आदर्श थाना बना सरपतहां, बाकी थानों के लिए प्रेरणा बन रहा है।

123 साल पुरानी इमारत बनी वीरानगी में पहचान



नेशनल अवार्ड विनर प्रोड्यूसर पीयूष सिंह की 'द नर्मदा स्टोरी' ने मचाया धमाल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर के लाल नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर पीयूष सिंह की चर्चित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' देश भर में चर्चा बटोरने के बाद अब जौनपुर में भी रिलीज हो रही है। फिल्म का विशेष प्रदर्शन जौनपुर के दर्शकों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक जैगम इमाम के निर्देशन में बनी है, जिन्होंने इससे पहले ही कई संवेदनशील और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है।

जौनपुर के लाल नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर पीयूष सिंह की चर्चित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' देश भर में चर्चा बटोरने के बाद अब जौनपुर में भी रिलीज हो रही है। फिल्म का विशेष प्रदर्शन जौनपुर के दर्शकों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक जैगम इमाम के निर्देशन में बनी है, जिन्होंने इससे पहले ही कई संवेदनशील और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है।

इसमें पहली बार एक वास्तविक आईपीएस अधिकारी सिमाला प्रसाद सिल्वर स्क्रीन पर अभिनय करती हुईं नजर आ रही हैं। उनके अभिनय की समीक्षकों ने विशेष सरहाना की है और दर्शकों ने भी उनके सहज और प्रभावशाली प्रदर्शन को खूब पसंद किया है। जौनपुर में फिल्म की रिलीज को लेकर प्रोड्यूसर पीयूष सिंह ने कहा, 'अपने शहर और

'हमारी पूरी टीम समीक्षकों और दर्शकों से मिल रहे प्यार और समर्थन से बेहद उत्साहित है। 'द नर्मदा स्टोरी' सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। हमारा प्रयास है कि यह फिल्म न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचे। 12 जून को रिलीज हुई 'द नर्मदा स्टोरी' की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। फिल्म में वहां की संस्कृति, सामाजिक परिस्थितियों और अपराध जगत के कई पहलुओं को बेहद वास्तविक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रिलीज के बाद फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और कई समीक्षकों ने इसकी कहानी, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय की एक सुर में प्रशंसा की है।

मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कई सिनेमाघरों में शो हासफुल चल रहे हैं और टिकटों की मांग लगातार बनी हुई है। फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह और अधिक शहरों तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। फिल्म के निर्देशक जैगम इमाम ने कहा,

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर के लाल नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर पीयूष सिंह की चर्चित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' देश भर में चर्चा बटोरने के बाद अब जौनपुर में भी रिलीज हो रही है। फिल्म का विशेष प्रदर्शन जौनपुर के दर्शकों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक जैगम इमाम के निर्देशन में बनी है, जिन्होंने इससे पहले ही कई संवेदनशील और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है।

जौनपुर के लाल नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर पीयूष सिंह की चर्चित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' देश भर में चर्चा बटोरने के बाद अब जौनपुर में भी रिलीज हो रही है। फिल्म का विशेष प्रदर्शन जौनपुर के दर्शकों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक जैगम इमाम के निर्देशन में बनी है, जिन्होंने इससे पहले ही कई संवेदनशील और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है।

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर के लाल नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर पीयूष सिंह की चर्चित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' देश भर में चर्चा बटोरने के बाद अब जौनपुर में भी रिलीज हो रही है। फिल्म का विशेष प्रदर्शन जौनपुर के दर्शकों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक जैगम इमाम के निर्देशन में बनी है, जिन्होंने इससे पहले ही कई संवेदनशील और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है।

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर के लाल नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर पीयूष सिंह की चर्चित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' देश भर में चर्चा बटोरने के बाद अब जौनपुर में भी रिलीज हो रही है। फिल्म का विशेष प्रदर्शन जौनपुर के दर्शकों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक जैगम इमाम के निर्देशन में बनी है, जिन्होंने इससे पहले ही कई संवेदनशील और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है।

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर के लाल नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर पीयूष सिंह की चर्चित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' देश भर में चर्चा बटोरने के बाद अब जौनपुर में भी रिलीज हो रही है। फिल्म का विशेष प्रदर्शन जौनपुर के दर्शकों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक जैगम इमाम के निर्देशन में बनी है, जिन्होंने इससे पहले ही कई संवेदनशील और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है।

भक्ति के साथ जवाबदेही का भी धाम है श्री काशी विश्वनाथ

सुरेश गांधी वाराणसी। देश इस समय मंदिरों में चढ़ावे की पारदर्शिता को लेकर नई बहस के दौर से गुजर रहा है। एक ओर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि को लेकर उठे विवाद सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम एक ऐसे उदाहरण के रूप में सामने है, जहां करोड़ों रुपये के चढ़ावे के बावजूद आज तक एक रुपये की हेरफेर की आरोप तक नहीं लगा। यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि उस विश्वास की रक्षा का मॉडल है, जिसे करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं।

काशी विश्वनाथ धाम में दान केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व भी है। यहां दानपात्र में गिरने वाले हर सिक्के और हर नोट का हिसाब उसी पारदर्शिता से रखा

जाता है, जैसी किसी बड़े बैंक या वित्तीय संस्थान में होती है। यही वजह है कि बाबा के दरबार में चढ़ावा हमेशा श्रद्धा का विषय रहा, कभी विवाद का नहीं।

विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष एवं वाराणसी के मंडलाध्यक्ष एस. राजलिंगम बताते हैं कि धाम में दान कई माध्यमों से प्राप्त होता है। श्रद्धालु 56 दान कुंडों में नकद दान करते हैं, वयूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान देते हैं, कार्यालय में रसीद लेकर दान जमा करते हैं और कई भक्त स्वर्ण, रजत एवं अन्य बहुमूल्य धातुएं भी अर्पित करते हैं। प्रत्येक माध्यम के लिए अलग और स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है।

खुले परिसर में होती है करोड़ों की गिनती। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि दान राशि की गिनती किसी बंद

कमरे में नहीं, बल्कि मंदिर परिसर स्थित सत्यनारायण मंदिर के खुले प्रांगण में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को की जाती है। यहां पूरी प्रक्रिया सबके सामने संपन्न होती है। गिनती के समय एक राजपत्रित अधिकारी (एसडीएम) की मौजूदगी अनिवार्य रहती है। मंदिर के स्वयंसेवक, समुदाय भवन से जुड़े सहयोगी तथा काशी में रहने वाली लगभग 20 से 25 माताएं दान की राशि को अलग-अलग श्रेणियों में छांटती हैं। इसके बाद बैंक के अधिकारी मौके पर ही लेखांकन करते हैं, लेजर में प्रविष्टियां दर्ज होती हैं और फिर पूरी राशि सीधे बैंक में जमा करा दी जाती है। बैंक की रसीद भी सरकारी अभिलेखों का हिस्सा बन जाती है।

डिजिटल दान सीधे खाते में आधुनिक तकनीक को भी धाम ने पूरी तरह अपनाया है। वयूआर



कोड से प्राप्त होने वाला प्रत्येक डिजिटल दान बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे बैंक के अधिकृत बैंक खाते में पहुंचता है। इससे नकदी प्रबंधन की आवश्यकता कम होती है और पारदर्शिता और अधिक मजबूत होती है।

सोने-चांदी का भी अलग प्रोटोकॉल श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए

30 करोड़ श्रद्धालु... 60 हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था काशी विश्वनाथ धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन भी बन चुका है। प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। सप्ताहांत में यह संख्या तीन से चार लाख तक पहुंच जाती है, जबकि महाशिवरात्रि, सावन, देव दीपावली जैसे विशेष अवसरों पर सात से आठ लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करते हैं। पिछले चार वर्षों में 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में शोश नवाया है। यदि भारत सरकार के पर्यटन संबंधी औसत व्यय के आंकड़ों के अनुसार प्रति श्रद्धालु खर्च का आकलन किया जाए तो यह संख्या वाराणसी की अर्थव्यवस्था में

हजारों करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारोबार जोड़ चुकी है। होटल, धर्मशाला, नाविक, ऑटो चालक, फूल-माला विक्रेता, प्रसाद दुकानदार, बुनकर, हस्तशिल्प, रेस्टोरेंट और स्थानीय व्यापार—सभी इस धार्मिक पर्यटन से लाभान्वित हो रहे हैं।

विश्वास की सबसे बड़ी पूंजी मंदिरों में आने वाला दान केवल मुद्रा नहीं होता, वह करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे पवित्र अंश होता है। इसलिए उसकी पारदर्शिता पर कोई भी प्रश्न पूरे धार्मिक तंत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

ऐसे समय में जब देश के कुछ प्रमुख धार्मिक संस्थानों की व्यवस्थाएं सवाल के घेरे में हैं, तब काशी विश्वनाथ धाम की यह व्यवस्था केवल वाराणसी ही नहीं, बल्कि देश के सभी बड़े मंदिरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनकर उभरी है। यहां हर नोट की गिनती है, हर सिक्के का हिसाब है और हर दान के पीछे श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा का संकल्प है। काशी ने सदियों से केवल अध्यात्म ही नहीं, व्यवस्था का भी संदेश दिया है। बाबा विश्वनाथ के दरबार की यह व्यवस्था बताती है कि पारदर्शिता केवल नियमों से नहीं आती, बल्कि नीयत, अनुशासन और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से आती है। यदि देश के सभी बड़े धार्मिक संस्थान इसी प्रकार खुली, जवाबदेह और तकनीक आधारित व्यवस्था अपनाए तो दान को लेकर उठने वाले अधिकांश विवाद स्वतः समाप्त हो सकते हैं। आखिर मंदिरों की सबसे बड़ी संपत्ति सोना-चांदी नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है।

हाईडिल जमीन विवाद-राजस्व विभाग की टीम ने किया मौका मुआयना



गौरतलब है की नगर पालिका परिषद के सभासद प्रेमचंद ने अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि विद्युत विभाग की हाईडिल की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहा है जिस पर प्रशासन ने रोक लगा दिया था जिसके बाद

प्रतिवादी अंकित कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां प्रतिवादी को राहत देते हुए एसडीएम शाहगंज को स्वयं मौजूद होकर जवाब देने को कहा था और डीएम की मौजूदगी में राजस्व टीम के

साथ जमीन की पैमाइश कराने की बात सामने आई थी। वहीं इस मामले में प्रतिवादी अंकित कुमार ने कहा की जमीन हमारी है जिसकी रजिस्ट्री 2017/18 में राजाराम से लिया गया था हमें सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जिस सभासद ने पीआईएल लगाई है। उसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। अंकित कुमार ने आगे बताया की उक्त भूमि नगर पालिका और खतौनी में दर्ज है। जिसका टैक्स भी नगर पालिका में भरा जाता है। बताते चले की इस मामले में एक मृतक व्यक्ति के नाम पर अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र पड़ा था। प्रतिवादी ने मज सारा साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किया तो कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया था।

युवती की फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रिश्ता तुड़वाने की साजिश रचने वाला गिरफ्तार

शाहगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सोशल मीडिया पर एक युवती की फोटो बंदनाम करने की नीयत से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने और उसकी शादी तुड़वाने की साजिश रचने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र के निवासी पीडित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि क्षेत्र के 'शालू' ने युवती की फोटो स्टेटस पर लगाने के साथ ही उसके होने वाले ससुराल पक्ष को भी अश्लील व भेदे संदेश भेजे, जिससे उसकी तय हो चुकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई। विरोध करने पर आरोपी ने पीडित पक्ष के साथ गाली-गलौज व अभद्रता की। मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शालू को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को चालान माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय केशवपुर का किया निरीक्षण



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने मंगलवार को धामपुर विकास खंड स्थित पीएम श्री विद्यालय बिहार एवं प्राथमिक विद्यालय केशवपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, निगुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित शिक्षण कार्य, स्वच्छता व्यवस्था एवं विद्यालयी अभिलेखों का अवलोकन किया। वीएसए ने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन किया तथा शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान आगामी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) की तैयारियों को समीक्षा करते हुए वीएसए ने विद्यालयों में योग कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नियमित योगाभ्यास करने, अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। विद्यार्थियों को योग अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर प्रकाश डाला। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है अपना दल : अनुप्रिया पटेल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें संगठन में पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है।

उन्होंने बताया कि पार्टी में महिलाओं को एक तिहाई आमंत्रण दिया गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में महिलाएं संगठनात्मक गतिविधियों और जनसरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सोमवार को रामनगर क्षेत्र के सरोना गांव में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य ललई सरोज की दादी जगदेई देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। अपना दल (एस) शुरू से ही महिलाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी द्वारा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में संगठन और अधिक सशक्त होकर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरगा। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रिकिल डेवलपमेंट कार्यक्रमों और रोजगार मेलों के जरिए लाखों युवाओं को लाभ मिला है, जिससे उनके भविष्य को नई दिशा प्राप्त हुई है।

जौनपुर की तीन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उतारेगी प्रत्याशी, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना: नदीम जावेद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक नदीम जावेद ने दावा किया है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जौनपुर जनपद की नौ विधानसभा सीटों में से कम से कम तीन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन करेगा और सरकार बनाने में सफल होगा। सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक नदीम जावेद ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय, बलाकाली और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में उत्तर प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। उनका आरोप था कि

किशोरों ने किया अनूठा प्रयास: मियावाकी कार्निवल से ऑटिज्म जागरूकता और समावेशिता का संदेश

इंदौर। विगत रविवार को इंदौर के बी जौन बिजनेस पार्क में किशोरों द्वारा अनोखा हामियावाकी कार्निवल का आयोजन किया गया। आज के समय ऑटिज्म बीमारी प्रति 60 में से एक बच्चे को है। जिसे माता पिता प्रारम्भ में नदेखना कर देते हैं। यह बात स्पेशल थैरेपिस्ट डॉ. गरिमा दीक्षित ने अपने मुख्य वक्तव्य में बताते हुए कहा कि इसके लिए प्रारम्भ में ही जागरूकता आवश्यक है। डॉ. अनुष्का जैन-ऑटिज्मल थैरेपिस्ट ने कहा कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो ऑटिज्म को अपनाते हैं और दूसरे वे जो रूढ़िवादी सोच के कारण इनको अपने बच्चों के साथ धुलने-मिलने नहीं देते। हमें इस दूरी को प्रारम्भ से मिटाना है। कार्यक्रम की निर्देशिका नेहा कनोडिया ने कार्निवल की भूमिका प्रस्तुत की। तारिणी कस्बेकर ने बताया कि कार्निवल का नाम मियावाकी विधि पर रखा गया है। इस विधि में पौधे साथ-साथ बोल जाते हैं और साथ-साथ बढ़ते हैं। उसी सिद्धांत पर बच्चों ने संदेश दिया कि हम भी सब एक साथ मिलकर बढ़ना



चाहते हैं। हमें जाति, नस्ल, आर्थिक स्थिति, समाज या ऑटिज्म के कारण भेदभाव नहीं करना है। हम सब साथ मिलकर बढ़ सकते हैं। कार्निवल का मुख्य विषय 'ऑटिज्म जागरूकता और समावेशिता' था। आयोजकों का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि हम अपने आस-पास रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझें। उनकी चुनौतियों को जानें। इस कार्निवल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यह हलबच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए, बच्चों का कार्यक्रम था। जिसे मुख्यतः अरिंजय तैरी, तारिणी कस्बेकर, शरण्या उपाध्याय और मिराया गांधी की टीम ने मिलकर सफलतापूर्वक संपन्न

किया। कार्यक्रम में ऑटिस्टिक बच्चों ने गायन और पियानो की प्रस्तुतियां दीं, भेलपुरी, चार्मस और बैक्स से बने उत्पादों के स्टॉल लगाए, लोगों से मिलना और पैसों का आदान-प्रदान सीखा। अन्य बच्चों में भोजन सामग्री, स्वहस्तनिर्मित उत्पाद, बैग कस्टमाइजेशन और मनोरंजक खेलों के स्टॉल लगाये। नेहा कनोडिया के निर्देशन और डॉ. अनुष्का जैन के मार्गदर्शन में उक्त किशोरों का गुप मिलकर समाजसेवा का यह कार्य कर रहा है। मियावाकी कार्निवल इसका प्रथम प्रयास है। इस गुप ने यह सावित कर दिया कि किशोर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं।

दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, एनसीडीसी निदेशक ने बताए एफपीओ सफलता के सूत्र



संवर्धन, वैल्यू एडिशन और लेखा-जोखा में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक संजय कुमार ने बताया कि सरकार व एनसीडीसी की मदद से एफपीओ संचालित कर किसानों का जीवन स्तर कैसे उंचा उठाया जा सकता है। एफपीओ निदेशक डी. अमित सिंह ने किसानों को एफपीओ से जोड़कर उनके उत्पादों के संरक्षण व लाभ पहुंचाने की रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि संगठित प्रयास से ही किसानों को उचित मूल्य मिल सकता है। एफपीओ संरक्षक ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। विशेष रूप से 50 एफपीओ के सीबीबीओ संजय सिंह के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में एनसीडीसी के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष शुक्ला, संरक्षक राम कुमार राय, मनोज कुमार, आरडी सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव समेत कई निदेशक मौजूद रहे। सभी ने कृषक उत्पादक संगठन टिकरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनेपद के कृषक उत्पादक संगठन टिकरी परिसर में रविवार को दो दिवसीय एफपीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। संरक्षक अनिल सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से आए 28 एफपीओ के निदेशक, सीडीओ व अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में एफपीओ के संवर्धन, प्रोजेक्ट विस्तार, गो

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनेपद के कृषक उत्पादक संगठन टिकरी परिसर में रविवार को दो दिवसीय एफपीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। संरक्षक अनिल सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से आए 28 एफपीओ के निदेशक, सीडीओ व अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में एफपीओ के संवर्धन, प्रोजेक्ट विस्तार, गो

जौनपुर: कृषक जागरूकता गोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बक्शा विकास खंड के ग्राम पंचायत हसरौली और बसारपुर में मंगलवार को आयोजित खेत बचाओ अभियान / विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसमें किसानों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उच्च वैज्ञानिक विधि से खेती करने का सुझाव दिए गए। उक्त कार्यक्रम का संचालन सहायक अधिकारी कृषि अनुराग सिंह ने किया जिसमें बताया विभागीय समस्त योजनाओं की जानकारी दी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत सभी किसानों को प्रेरित किया कि अपनी अपनी ई-केवाईसी जरूर कराएँ जो की प्रत्येक वर्ष कराना अनिवार्य हो गया है। कार्यक्रम में धान की डी.एस.आर. विधि से बुवाई कर किसान भाई कम लागत और कम पानी में अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं साथ ही उन्नत सिंचाई पद्धतियों, कृषि निवेश व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में किसानों को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त किसानों की फार्म रजिस्ट्री तैयार करने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए शत-प्रतिशत लोग इसमें अपना पंजीकरण कराएँ जिससे आगामी

समस्त योजनाओं का लाभ अनवरत रूप प्राप्त कर सकें। हसरौली में कार्यक्रम की अध्यक्षता अनजय सिंह (निर्माण समिति अध्यक्ष बक्शा) ने तथा बसारपुर में ग्राम प्रधान संजय कुमार ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बक्शा डा सुरेश कुमार कनौजिया जी ने बताया कि मिट्टी, पानी और किसान तीनों को बचाना। आज रासायनिक खाद और कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है और भूजल तेजी से नीचे जा रहा है। इसलिए प्राकृतिक खेती अपनाएं, गोबर-गोमूत्र से बनी जैविक खाद डालें, फसल चक्र अपनाएं और ड्रिप-रिस्कन जैसी जल-बचत तकनीक लगाएँ। स्वस्थ मिट्टी से ही अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल से किसान खुशहाल होगा और तभी देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसीलिए शासन द्वारा 13 से 27 जून 2026 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाकर किसानों को खेत बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अगले वक्ता के रूप में उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉ रमेश चंद्र यादव के कृषि विभाग जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए किसानों को पीएम किसान सम्मान

निधि, फसल बीमा योजना व मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभों से अवगत कराया। कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजीव कुमार सिंह, डॉ. हरिओम वर्मा ने प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर व बारीकियां की जानकारी उपलब्ध कराएँ। उद्यान निरीक्षक राजकुमार, जितेन्द्र कुमार सिंह कृषि रक्षा एवं तकनीकी सहायक अश्वनी कुमार सिंह और धर्मेश कुमार पटेल भारी संख्या में आएँ हुए किसान बन्धु जिसमें लालमनि, रामप्रसाद, विमल सिंह, गौरव सिंह, रानू कुमार, हरेंद्र कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। शासन के निर्देश पर 13 जून 2026 से 27 जून 2026 के मध्य संचालित होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान-2026 की जनपद में आयोजित होने वाली कार्यगोष्ठी में केवीके तथा प्रदेश सरकार के कृषि, सहकारी, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई/नलकूप एवं लोड बैंक मैनेजर/सीडीओम नाबाई संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षक की भूमिका में उपस्थित होकर शासन की किसानों-मुखी योजनाओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जैसी तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई।

चोलापुर पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई, हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार



वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के कमिश्नर पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध शस्त्रों की खरीद-फरोख्त और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चोलापुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मंगलवार को कटारी ब्लॉक के पीछे स्थित अंडरपास के पास से सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में रैचनपुर निवासी अखिलेश उर्फ मोनु राजभर (27), अटुएसुआ निवासी अरुण राजभर (21), धौरहरा (चौबेपुर) निवासी हिमांशु कुमार उर्फ सनी (28), शिवरामपुर निवासी आभाष सिंह (23), नेहाया विशाल सिंह (19), गोसाईपुर मोहान निवासी अनिकेत चौहान (20) तथा गुरवट निवासी नमन मिश्रा उर्फ अस्तीशू (25) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक .32 बोर रिवाल्वर, छह जिंदा कारतूस (.32 बोर), एक 7.65 एएमएम पिस्टल व दो कारतूस, एक .315 बोर तमंचा व तीन कारतूस, एक 9 एएमएम पिस्टल व दो जिंदा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल तथा विभिन्न कंपनियों के छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वे अवैध हथियार अपने पास रखते थे और लोगों को डराकर चोरी, छिन्ती तथा लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। साथ ही अधिक पैसा मिलाने पर तमंचा, पिस्टल और कारतूस बेचने का भी काम करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात की तैयारी में जुटे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई।

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के कमिश्नर पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध शस्त्रों की खरीद-फरोख्त और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चोलापुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मंगलवार को कटारी ब्लॉक के पीछे स्थित अंडरपास के पास से सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में रैचनपुर निवासी अखिलेश उर्फ मोनु राजभर (27), अटुएसुआ निवासी अरुण राजभर (21), धौरहरा (चौबेपुर) निवासी हिमांशु कुमार उर्फ सनी (28), शिवरामपुर निवासी आभाष सिंह (23), नेहाया विशाल सिंह (19), गोसाईपुर मोहान निवासी अनिकेत चौहान (20) तथा गुरवट निवासी नमन मिश्रा उर्फ अस्तीशू (25) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक .32 बोर रिवाल्वर, छह जिंदा कारतूस (.32 बोर), एक 7.65 एएमएम पिस्टल व दो कारतूस, एक .315 बोर तमंचा व तीन कारतूस, एक 9 एएमएम पिस्टल व दो जिंदा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल तथा विभिन्न कंपनियों के छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वे अवैध हथियार अपने पास रखते थे और लोगों को डराकर चोरी, छिन्ती तथा लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। साथ ही अधिक पैसा मिलाने पर तमंचा, पिस्टल और कारतूस बेचने का भी काम करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात की तैयारी में जुटे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई।

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के कमिश्नर पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध शस्त्रों की खरीद-फरोख्त और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चोलापुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मंगलवार को कटारी ब्लॉक के पीछे स्थित अंडरपास के पास से सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में रैचनपुर निवासी अखिलेश उर्फ मोनु राजभर (27), अटुएसुआ निवासी अरुण राजभर (21), धौरहरा (चौबेपुर) निवासी हिमांशु कुमार उर्फ सनी (28), शिवरामपुर निवासी आभाष सिंह (23), नेहाया विशाल सिंह (19), गोसाईपुर मोहान निवासी अनिकेत चौहान (20) तथा गुरवट निवासी नमन मिश्रा उर्फ अस्तीशू (25) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक .32 बोर रिवाल्वर, छह जिंदा कारतूस (.32 बोर), एक 7.65 एएमएम पिस्टल व दो कारतूस, एक .315 बोर तमंचा व तीन कारतूस, एक 9 एएमएम पिस्टल व दो जिंदा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल तथा विभिन्न कंपनियों के छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वे अवैध हथियार अपने पास रखते थे और लोगों को डराकर चोरी, छिन्ती तथा लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। साथ ही अधिक पैसा मिलाने पर तमंचा, पिस्टल और कारतूस बेचने का भी काम करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात की तैयारी में जुटे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई।

फादर्स डे पर काई इंडिया ने पेश किए प्रीमियम ग्रूमिंग और किचन एसेंशियल्स

मुंबई। पिता हमारे जीवन में केवल एक अभिभावक की भूमिका नहीं निभाते, बल्कि वे प्रेरणा, अनुशासन, भरोसे और समर्पण की मिसाल भी होते हैं। परिवार की जिम्मेदारियों से लेकर अपने व्यक्तिगत शौक और रुचियों तक, वे हमें काम को पूरी लगन और बारीकी से पूरा करने में विश्वास रखते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए काई इंडिया ने फादर्स डे के अवसर पर अपने चुनिंदा प्रीमियम ग्रूमिंग और किचन एसेंशियल्स को प्रमुखता से पेश किया है। जापान की

800 वर्षों से अधिक पुरानी ब्लेड मैकिंग विरासत से प्रेरित काई आज दुनिया भर में अपनी बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। पारंपरिक जापानी विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीक का मेल काई के उत्पादों को खास बनाता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहत अनुभव और परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। परफेक्ट ग्रूमिंग कर्मीनियन-जो पिता अपनी ग्रूमिंग को लेकर सजग हैं और रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहतर गुणवत्ता को महत्व देते हैं, उनके

लिए काई ऑफर 5 ब्लेड रेजर पैक एक बेहतरीन विकल्प है। एडवांस्ड 5 ब्लेड सिस्टम से लेश यह रेजर स्मूद, क्लोज और आरामदायक शेविंग प्रदान करता है। मल्टी लेयर्ड कोटेड ब्लेड्स इसकी धार और टिकाऊपन को बेहतर बनाते हैं, जबकि इसका एरॉनॉमिक डिजाइन बेहतर ग्रिप और कंट्रोल सुनिश्चित करता है। उन्नत जापानी टेक्नोलॉजी से विकसित यह रेजर त्वचा पर कम दबाव डालते हुए बेहतर शेविंग अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है।



हूए सरोज हत्याकांड का भी जिज्ञा करते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं आम जनता के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं। उन्होंने इन मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता बताई। पत्रकार वार्ता के दौरान नदीम जावेद ने राम मंदिर के दानपात्र से सक्ति चोरी की घटना का भी उल्लेख किया और मामले के शीघ्र खुलासे की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी घटनाओं की पारदर्शी जांच होना आवश्यक है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगा और प्रदेश की

जनता बदलाव के पक्ष में निर्णय लेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना मजबूत है। पत्रकार वार्ता के दौरान शहर काँग्रेस के जिला उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा, अध्यक्ष आरिफ खान, प्रेस सचिव सत्यवीर सिंह, राजकुमार मिश्रा, राजकुमार गुप्ता, लाल प्रकाश पाल, देवराज पाण्डे, जैनव हैदर, शानवजाह मंजूर, मोहम्मद सालिम, सादाब अहमद सद्दाम प्रशान, प्रमोद यादव, सानु पटान शशांक, सोमनकर इकबाल हुसैन, मोहम्मद ताहिर और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और जनसंपर्क अभियान तेज करने की बात कही।

हूए सरोज हत्याकांड का भी जिज्ञा करते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं आम जनता के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं। उन्होंने इन मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता बताई। पत्रकार वार्ता के दौरान नदीम जावेद ने राम मंदिर के दानपात्र से सक्ति चोरी की घटना का भी उल्लेख किया और मामले के शीघ्र खुलासे की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी घटनाओं की पारदर्शी जांच होना आवश्यक है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगा और प्रदेश की